जुलाई 2024 ■ वर्ष : 33 ■ अंक : 11 ₹135

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

50 महत्वपूर्ण टॉपिक

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

मॉडल प्रश्नों के साथ

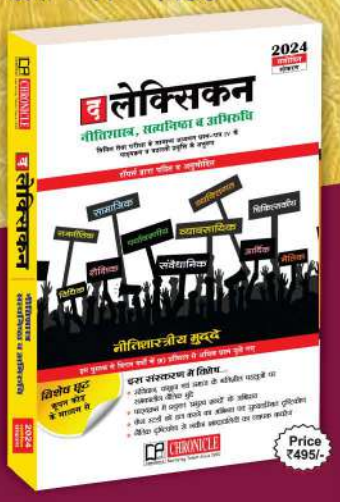

हल प्रश्न-पत्र

UPSC

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2024

विशेष आलेख

- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर
  भारत के सामाजिक रूपांतरण का एक मूलभूत चालक
- जलवायु परिवर्तन : महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव
  भेद्यताओं को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता
- भारत में ठोस अपशिष्ट का कुप्रबंधन
  सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा
- भारत में एफडीआई प्रवाह
  नवीन रुझान, चुनौतियां तथा आगे की राह
- भारत में प्रतिपूरक वनरोपण
  महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
- भारत में औषधि क्षेत्र का विनियमन
  वर्तमान व्यवस्था, चुनौतियां एवं निहितार्थ
- बिम्सटेक
  बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में BRI का महत्वपूर्ण विकल्प

अन्य आकर्षण

न्यूज बुलेट्स

पत्रिका सार : मई 2024 में प्रकाशित पत्रिकाओं पर आधारित

चर्चित शब्दावली

संसद प्रश्नोत्तरी

फैक्ट शीट : वस्त्र एवं परिधान तथा गेमिंग क्षेत्र

समसामयिक प्रश्न

वनलाइनर करेंट अफेयर्स

जुलाई 2024 सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

जुलाई 2024
❑ वर्ष 33 ❑ अंक 11

इस अंक में

62

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा विशेष

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

इस विशेष खंड में हम अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के 50 महत्वपूर्ण विषयों (Topics) पर सारगर्भित एवं व्यापक सामग्री का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं। हमारी विशेषज्ञ टीम द्वारा इन विषयों की पहचान विगत वर्षों के प्रश्नों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के आधार पर की गई है। विषयों के केवल उन आयामों को ही शामिल किया गया है, जिनकी आगामी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। इस विशेष खंड में हम प्रत्येक विषय के पश्चात एक अति संभावित मॉडल-प्रश्न दे रहे हैं। ये प्रश्न आपको परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में मददगार होंगे।

सामयिक आलेख

07 डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर : भारत के सामाजिक रूपांतरण का एक मूलभूत चालक
09 भारत में ठोस अपशिष्ट का कुप्रबंधन : सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा
12 जलवायु परिवर्तन का महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव : भेद्यताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता

इन फोकस

14 बिम्सटेक : बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बीआरआई का महत्वपूर्ण विकल्प
15 भारत में FDI प्रवाह : नवीन रुझान, चुनौतियां तथा आगे की राह
16 भारत में प्रतिपूरक वनरोपण : महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
17 भारत में औषधि क्षेत्र का विनियमन : वर्तमान व्यवस्था, चुनौतियां एवं निहितार्थ

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य

राजव्यवस्था एवं शासन 19
राष्ट्रीय मुद्दे 20
बैठक एवं सम्मेलन 21
न्यायपालिका 22
राष्ट्रीय सुरक्षा 24

सार्वजनिक नीति

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम का एक दशक पूर्ण 25
सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी 25
कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध के पालन से संबंधित चेतावनी 26
अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) अधिनियम, 2023 26

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक 27
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक 29

सामाजिक परिदृश्य

सामाजिक न्याय 33
सामाजिक-आर्थिक विकास 34
भारत में सामाजिक समस्याएं 34

कल्याणकारी योजनाएं

PM-WANI योजना की प्रगति 36
उत्तर-पूर्वी राज्यों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 36
भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण 37
आदिवासियों हेतु आवास योजना की चुनौतियां 37
'नाबालिग लड़की पीड़ित सहायता योजना' में विसंगतियां 37

विरासत एवं संस्कृति

ऐतिहासिक व्यक्तित्व 38
कला एवं संस्कृति 39
ऐतिहासिक साक्ष्य 40

आर्थिक परिदृश्य

उद्योग 41
बुनियादी ढांचा 43
संसाधन 44
विदेशी व्यापार और एफडीआई 44
बैंकिंग और वित्त 46
भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं 47

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

वैश्विक मुद्दे 48
अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते 48
अंतरराष्ट्रीय संबंध 51
मानचित्र के माध्यम से 51

पर्यावरण एवं जैव विविधता

जैव विविधता 52
सतत विकास 53
प्रदूषण 53
जलवायु परिवर्तन 55
आपदा प्रबंधन 56
पर्यावरण संरक्षण 56

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष विज्ञान 57
जैव प्रौद्योगिकी 59
रक्षा प्रौद्योगिकी 61
भू-विज्ञान 61

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

राज्य परिदृश्य

मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 105
राजस्थान 106
गुजरात 106
छत्तीसगढ़ 106
मणिपुर 106
सिक्किम 106

न्यूज बुलेट्स 107-119

लघु संचिका

चर्चित व्यक्तित्व/नियुक्ति 120
निधन 120
पुरस्कार एवं सम्मान 121

खेल परिदृश्य

टेनिस 123
मुक्केबाजी 123
क्रिकेट 123
एथलेटिक्स 123

परीक्षा सार 124-145

UPSC सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2024
व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं साइंस रिपोर्टर 146-154

चर्चित शब्दावली 155

संसद प्रश्नोत्तरी 156

फैक्ट शीट 157

समसामयिक प्रश्न 158-159

वनलाइनर करेंट अफेयर्स 160-162

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

भारत के सामाजिक रूपांतरण का एक मूलभूत चालक

• डॉ. अमरजीत भार्गव

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के उद्भव से भारत में ई-गवर्नेंस प्रयासों को व्यापक बल मिला है। इससे नागरिक, सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला तक ऑनलाइन पहुंच बनाने में सक्षम हुए हैं। सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना DPI सभी व्यक्तियों एवं व्यवसायों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य कर रहा है। भारत की डीपीआई पहल, जिसे 'इंडिया स्टैक' के रूप में जाना जाता है, उत्पादकता में वृद्धि, दक्षता में सुधार तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने में सहायक रही है।

हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत के नेतृत्व में 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (DPI) पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि भारत की प्रगति इस बात का उदाहरण है कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सामाजिक परिवर्तन और प्रगति का एक बुनियादी चालक है।

साथ ही, यदि समावेशी तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो यह समान अवसर प्रदान करता है। भारत ने DPI-केंद्रित रणनीति अपनाकर उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। भारत में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) की स्थापना एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी के रूप में की गई है, जो विश्व भर के कई देशों, निगमों और स्टार्ट-अप्स के लिए एक बेंचमार्क बन गई है। इस प्रकार, सामाजिक रूपांतरण में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्व तथा चुनौतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है?

- जी-20 फ्रेमवर्क के तहत अपनाई गई परिभाषा के अनुसार 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (DPI) 'साझा डिजिटल सिस्टम' (Shared Digital Systems) का एक सेट है, जिसका उपयोग विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास, प्रतिस्पर्धा, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
- HTTP, HTML और SMTP जैसे सामान्य प्रोटोकॉल द्वारा संचालित इंटरनेट सेवाएं तथा GSM, SMS, CDMA एवं IEEE 802.11 जैसी टेलीकॉम सुविधाएं 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (DPI) के प्रमुख उदाहरण हैं।
- दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (DPI) एक 'ओपन-सोर्स पहचान प्लेटफॉर्म' (Open-Source Identity Platform) है। इसकी मदद से विभिन्न एप्लिकेशन एवं अन्य उत्पादों का निर्माण करके सरकारी और निजी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है।
- पहचान, भुगतान एवं डेटा प्रबंधन DPI के 3 व्यापक उद्देश्य हैं। भारत में डिजिटल पहचान-पत्र के लिए आधार-कार्ड, डिजिटल भुगतान हेतु यूपीआई (UPI) तथा डेटा प्रबंधन हेतु सहमति-आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली [Data Empowerment and Protection Architecture (DEPA)] का विकास किया गया है।
- इस प्रकार, भारत अपने 'इंडिया स्टैक' प्लेटफॉर्म के माध्यम से DPI के सभी तीन मूलभूत स्तंभों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है।

भारत का DPI: एक वैश्विक रोल-मॉडल

- भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) को 'इंडिया स्टैक' के नाम से जाना जाता है। यह देश में नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ है। DPI ने बाजारों का विस्तार करने, वित्तीय समावेशन अंतराल को कम करने, सरकारी राजस्व को बढ़ाने तथा इसकी व्यय दक्षता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- वित्तीय एवं सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के प्रभावी उपयोग के कारण सितंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा भारत की सराहना की गई थी।
- सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर प्रमुखता से चर्चा की गई थी। शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी किये गए दिल्ली घोषणा-पत्र में डिजिटल पहुंच में असमानताओं को दूर करने तथा सुधार की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए DPI को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया था।
- 22 नवंबर, 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत के नेतृत्व वाली दो पहलों के आरंभ की घोषणा की गई थी- ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी (GDPIR) तथा DPI कार्यान्वयन को तेज करने के लिए एक 'सोशल इम्पैक्ट फंड'। नवंबर 2023 तक GDPIR में 16 देशों के 54 DPI शामिल हो चुके हैं।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रमुख चुनौतियां

- डिजिटल विभाजन तथा डिजिटल निरक्षरता के कारण देश में अनेक लोगों की अभी भी स्मार्टफोन एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच नहीं है। इंडिया इनइक्वैलिटी रिपोर्ट, 2022 में बताया गया है कि भारत की केवल 31% ग्रामीण आबादी तथा 67 प्रतिशत शहरी आबादी ही इंटरनेट का उपयोग करती है।
- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तक लोगों की पहुंच में वृद्धि के साथ डेटा लीक और चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आईसीएमआर डेटा लीक की घटना इसका प्रमुख उदाहरण है, इससे डेटा गोपनीयता को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।
- मोबाइल तथा इंटरनेट के वर्तमान युग में साइबर हमलों की प्रवृत्ति में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। साइबर अपराध के कारण अनेक बार लोगों को वित्तीय हानि का सामना भी करना पड़ता है।
- यूपीआई को छोड़कर अनेक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जिनके मध्य 'इंटरऑपरेबिलिटी' संभव नहीं है। इससे सेवाओं तक लोगों की निर्बाध पहुंच में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

भारत में ठोस अपशिष्ट का कुप्रबंधन

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा

• संपादकीय डेस्क

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) की प्रक्रिया में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करने, उपचारित करने, निपटान करने तथा पुनर्चक्रण करने की व्यवस्थित शृंखला को शामिल किया जाता है। कानूनी हितधारकों के बीच अस्पष्टता, जागरूकता की कमी तथा अनियमित विनियामकीय प्रवर्तन ठोस अपशिष्ट के कुशल प्रबंधन में प्रमुख बाधाएं हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। साथ ही, तकनीकी एवं आर्थिक घटकों के कुशल संयोजन से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों को टिकाऊ एवं व्यवहार्य बनाया जा सकता है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 'टर्निंग रबिश इन टू ए रिसोर्स: ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक, 2024' नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जनसंख्या का एक तिहाई से अधिक भाग ठोस अपशिष्ट के साथ जीवन जीने को विवश है। रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि ठोस अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा वर्ष 2023 में 2.3 बिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 3.8 बिलियन टन हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अनुमानित रूप से 540 मिलियन टन नगरीय ठोस अपशिष्ट, जो वैश्विक कुल अपशिष्ट का 27% है, एकत्र नहीं किया जा रहा है। उप-सहारा अफ्रीका तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया में उत्पन्न होने वाले कचरे का केवल 36% और 37% ही एकत्र किया जा रहा है। हाल ही में एक अन्य घटनाक्रम के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नई दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की खराब व्यवस्था की आलोचना की गई।

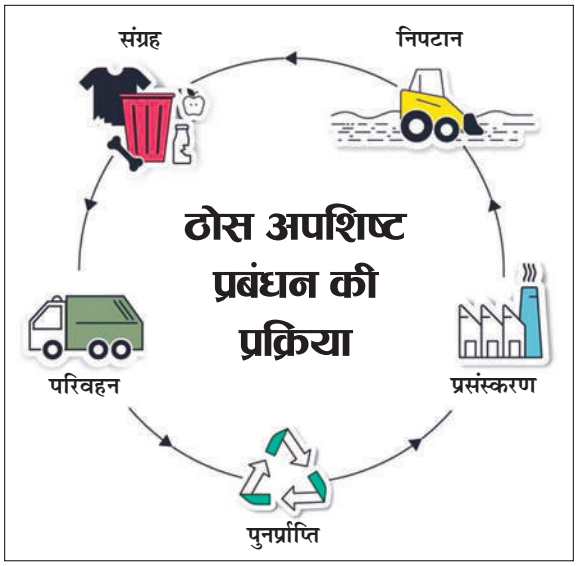

* राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 3,800 टन (TPD) से अधिक ठोस अपशिष्ट अनुपचारित रह जाता है। यह अपशिष्ट लैंडफिल में पहुंचकर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के समक्ष खतरे उत्पन्न करता है।
  - ठोस अपशिष्ट कुप्रबंधन की समस्या की व्यापकता को देखते हुए भारत में इसके स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किये गए प्रयासों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

भारत में ठोस अपशिष्ट: एक अवलोकन

* ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
* कुल उत्पन्न अपशिष्ट में से केवल 43 मिलियन टन ही एकत्रित किया जाता है, जिसमें से 12 मिलियन टन अपशिष्ट का निपटान से पूर्व उपचार किया जाता है, तथा शेष 31 मीट्रिक टन को अपशिष्ट-क्षेत्रों/लैंडफिल में एकत्र किया जाता है।
* भारत के 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB) के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2030 तक देश में वार्षिक अपशिष्ट उत्पादन बढ़कर 165 मिलियन टन हो जाएगा। जोखिमयुक्त, प्लास्टिक, ई-अपशिष्ट और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निष्कर्षण में भी आनुपातिक रूप से वृद्धि होने की संभावना है।
* जर्नल ऑफ अर्बन मैनेजमेंट (दिसंबर 2021) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, देश में वार्षिक रूप से उत्पन्न होने वाले 62 मिलियन टन अपशिष्ट में से 7.9 मिलियन टन जोखिमयुक्त अपशिष्ट, 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट, 1.5 मिलियन टन ई-अपशिष्ट तथा 0.17 मिलियन टन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शामिल हैं।

खराब अपशिष्ट प्रबंधन या अपशिष्ट कुप्रबंधन के प्रतिकूल प्रभाव

* **स्वास्थ्य समस्याएं:** ठोस अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अपशिष्ट का खुले में दहन करने से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है तथा दीर्घकाल में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।
  - इसी प्रकार, ठोस अपशिष्ट के अनियमित संग्रहण से चूहे एवं मच्छरों जैसे बीमारियों के वाहकों का प्रसार हो सकता है।
* **पर्यावरणीय समस्याएं:** ठोस अपशिष्ट की अवैज्ञानिक डंपिंग से मृदा एवं भू-जल प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है। इससे न केवल आस-पास का पर्यावरण दूषित होता है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।
  - लैंडफिल स्थलों पर मीथेन तथा कार्बन जैसी हानिकारक गैसों की अधिकता होती है, जिससे वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है।
  - वर्षा ऋतु में भूमि-आधारित अपशिष्ट समुद्र में प्रवाहित हो जाता है, इससे समुद्री अम्लीकरण एवं प्रदूषण में वृद्धि होती है।

जलवायु परिवर्तन : महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव

भेद्यताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता

• आलोक सिंह

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, किसी आपदा के दौरान महिलाओं और बच्चों की मृत्यु की संभावना पुरुषों की तुलना में 14 गुना अधिक होती है। जलवायु परिवर्तन, मौजूदा भेद्यताओं एवं असमानताओं को बढ़ाता है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, लोचशीलता बढ़ाने तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु तत्काल एवं लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस होती है।

हाल ही में एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन पर किये गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में महिलाएं और बच्चे जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। अध्ययन में यह भी पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चों में बौनेपन, अल्प वजन जैसे जोखिमों की संभावना बनी रहती है।

* विश्व में चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु-प्रेरित प्राकृतिक खतरों में वृद्धि देखी जा रही है, जो सुभेद्य आबादी (Vulnerable Population) को काफी हद तक प्रभावित कर रही है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) की 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के 75% जिले बाढ़, सूखे और चक्रवात जैसी जल-मौसम संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। ये परिवर्तन महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करते हैं।
* राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के पांचवे दौर के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में आधी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे इस प्रकार के जोखिमों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाएं लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि करती हैं और जल चक्र पैटर्न को प्रभावित कर सुरक्षित पेयजल तक पहुंच को और अधिक सीमित करती हैं। इन कमजोरियों को दूर करना न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

जलवायु परिवर्तन महिलाओं और बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करता है?

जलवायु परिवर्तन महिलाओं और बच्चों को निम्नलिखित रूप से प्रभावित करता है:

* **लैंगिक असमानता में वृद्धि:** जलवायु परिवर्तन मौजूदा लैंगिक असमानताओं को बढ़ाता है तथा महिलाओं और लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता तथा भोजन, जल और ईंधन सुरक्षित करने में उनकी भूमिका के कारण उन्हें अपनी आजीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित अद्वितीय खतरों का सामना करना पड़ता है।
* **महिलाओं पर बढ़ता बोझ:** निम्न तथा निम्न-मध्यम आय वाले देशों में महिलाएं, कृषि क्षेत्र में संलग्न होती हैं। ऐसे में जलवायु-प्रेरित सूखे और अनियमित वर्षा के कारण महिलाओं के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है तथा अपने परिवार की मदद करने के लिए अक्सर लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है।
* **हिंसा का खतरा:** जलवायु परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तनावों को बढ़ाता है, विशेष रूप से कमजोर और संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में। इससे मानव तस्करी और बाल विवाह सहित लिंग आधारित हिंसा के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
* **आपदा प्रभाव:** महिलाओं के आपदाओं से बचने की संभावना कम होती है तथा सूचना, गतिशीलता, निर्णय लेने और संसाधनों तक पहुंच में असमानताओं के कारण उनके आपदाओं से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। आपदा के पश्चात, उन्हें राहत और सहायता प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे असुरक्षा का चक्र चलता रहता है।
* **स्वास्थ्य जोखिम:** जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सीमित करके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित जोखिमों को बढ़ाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण 'मृत शिशु जन्म' (stillbirth) की घटनाएं बढ़ जाती हैं तथा मलेरिया और जीका वायरस जैसी वेक्टर जनित बीमारियां फैलने से मातृ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन महिलाओं और लड़कियों के लिए अन्य असमानताओं के साथ कैसे जुड़ा हुआ है?

* **अंतरविषयक प्रभाव (Intersectional Impact):** अंतरविषयक नारीवाद (Intersectional Feminism) सिद्धांत के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विभिन्न असमानताओं के विभिन्न रूप अक्सर एक साथ काम करते हैं और एक-दूसरे को बढ़ाते हैं।
* **आर्थिक असमानता:** महिलाओं के पास अक्सर आर्थिक संसाधनों और अवसरों तक कम पहुंच होती है। उनकी अनौपचारिक और कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने की अधिक संभावना रहती है तथा यह अनौपचारिक क्षेत्र जलवायु प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है।
* **शैक्षिक असमानताएं:** जलवायु परिवर्तन शिक्षा को बाधित कर सकता है; लड़कियों के संबंध में यह तथ्य विशेष रूप से सत्य है। इन्हें जलवायु-प्रेरित संकटों के दौरान घरेलू और कृषि कार्यों में मदद करने के लिए स्कूल जाने से रोक दिया जाता है।
* **स्वास्थ्य असमानताएं:** महिलाओं और लड़कियों को जलवायु परिवर्तन से अधिक स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, वेक्टर जनित बीमारियों का बढ़ता जोखिम तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जोखिम शामिल हैं।
* **सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंड:** समाज के विभिन्न लैंगिक मानदंड एवं भूमिकाएं महिलाओं और लड़कियों पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। यह बोझ जलवायु संकटों के दौरान और भी अधिक बढ़ जाता है।
* **राजनीतिक सशक्तीकरण का अभाव:** महिलाओं को अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कम प्रतिनिधित्व मिलता है, जिसका

in फोकस

- बिम्सटेक : बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बीआरआई का महत्वपूर्ण विकल्प
- भारत में FDI प्रवाह : नवीन रुझान, चुनौतियां तथा आगे की राह
- भारत में प्रतिपूरक वनरोपण : महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
- भारत में औषधि क्षेत्र का विनियमन : वर्तमान व्यवस्था, चुनौतियां एवं निहितार्थ

बिम्सटेक

बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बीआरआई का महत्वपूर्ण विकल्प

20 मई, 2024 को बिम्सटेक ने अपने पहले चार्टर के लागू होने के साथ एक 'कानूनी व्यक्तित्व' (Legal Personality) का दर्जा हासिल कर लिया है। इसके पश्चात अब बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) नए सदस्यों और पर्यवेक्षकों को शामिल कर सकता है। यह चार्टर बिम्सटेक को अन्य देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ संरचित राजनयिक संवाद में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। इससे व्यापक जुड़ाव और साझेदारी के रास्ते खुलेंगे, जिससे बिम्सटेक मंच के भू-राजनीतिक महत्व में वृद्धि होगी।

- वर्तमान में चीन का उभार एवं इसकी बढ़ती आक्रामकता भारत के लिए चिंता का विषय है तथा चीन के द्वारा अपनी 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' (BRI) के माध्यम से अपने प्रभाव में वृद्धि की जा रही है। BRI के सदस्य देशों पर अत्यधिक 'कर्ज भार' इसकी प्रमुख चुनौती बन गई है। ऐसी स्थिति में BIMSTEC बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय एकजुटता को संबोधित करने का एक विकल्प सिद्ध हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में BIMSTEC की प्रासंगिकता तथा इसके मार्ग की चुनौतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

बिम्सटेक तथा इसका वर्तमान स्वरूप

- बैंकॉक घोषणा द्वारा जून 1997 में स्थापित बिम्सटेक एक आर्थिक ब्लॉक है। इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में है।
- आरंभ में इसके चार सदस्य थे- बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। नेपाल 1998 में एक पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुआ और बाद में फरवरी 2004 में भूटान तथा नेपाल को एक साथ पूर्णकालिक सदस्यता प्रदान की गई।
- इस प्रकार, बिम्सटेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं।
- बिम्सटेक का लक्ष्य सहयोगात्मक प्रयासों, क्षेत्रीय संसाधनों तथा भौगोलिक लाभों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर वैश्वीकरण के प्रभावों को संबोधित करना है।
- उपर्युक्त प्रथम चार्टर में 'कानूनी व्यक्तित्व' प्राप्त करने का अर्थ है कि संगठन को अपने सदस्य देशों से अलग, अपने आप में एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- चार्टर लागू होने से सदस्य देश सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार, कृषि, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा लोगों से लोगों के मध्य संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अधिक संरचित और संगठित सहयोग में संलग्न हो सकते हैं।
- यह चार्टर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के भीतर गहन एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। सहयोग के लिए सामान्य लक्ष्य और तंत्र स्थापित करके, यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

बिम्सटेक की ओर भारत का रणनीतिक फोकस क्यों?

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के अस्तित्व में आने के तीन दशकों के बाद भी इसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है।
  - पिछले 30 वर्षों में द्विपक्षीय या आंतरिक राजनीतिक कारणों से SAARC की वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठक को 11 बार स्थगित किया गया है।
  - आतंकवाद के अलावा अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर SAARC की प्रासंगिकता संदेह के घेरे में आ गई है।
- वर्ष 2016 के बाद से SAARC की निष्क्रियता की स्थिति में BIMSTEC एक वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच के रूप में उभरा है। भारत भी इसकी वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठकों में नियमित रूप से भाग ले रहा है।
- किसी भी अन्य नवीन क्षेत्रीय समूह के गठन की तुलना में दक्षिण एशिया के देशों द्वारा BIMSTEC का चुनाव करना इसके बढ़ते महत्व को प्रदर्शित करता है। BIMSTEC के सदस्य देश आपसी मुद्दों पर अधिक सहयोगी रुख अपना रहे हैं।

BRI के विकल्प के रूप में BIMSTEC

- बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में BIMSTEC को चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' (BRI) के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और आर्थिक विकास को समर्थन देना है।
- BRI की ऋण व्यवस्था अधिक कठोर है, इसमें शामिल होने के पश्चात सदस्य देशों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि वर्ष 2023 में आयोजित BRI के तीसरे फोरम में राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली थी।
- वर्ष 2019 की तुलना में, फोरम में भाग लेने वाले राष्ट्रीय नेताओं की संख्या 37 से घटकर 2023 में केवल 24 रह गई थी। यह स्थिति BRI की घटती प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है।
- श्रीलंका BIMSTEC और BRI दोनों का सदस्य है। कुछ समय पूर्व, श्रीलंका द्वारा स्वतंत्रता के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट का अनुभव किया गया।

राजव्यवस्था एवं शासन

- किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु 3 माह की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- मतदान डेटा के संबंध में चिंताएं तथा फॉर्म 17सी
- 'पलियार जनजाति' को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता

राष्ट्रीय मुद्दे

- मानक आवश्यक पेटेंट : नियामक चुनौतियां

बैठक एवं सम्मेलन

- महत्वपूर्ण खनिजों पर सम्मेलन
- आपराधिक न्याय प्रणाली पर सम्मेलन

न्यायपालिका

- सेलिब्रिटी एवं इन्फ्लुएंसर्स, भ्रामक विज्ञापनों हेतु समान रूप से जिम्मेदार
- सार्वजनिक बैंक लुक-आउट सर्कुलर की सिफारिश नहीं कर सकते
- नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश
- कलकत्ता हाई कोर्ट ने समाप्त किया कई वर्गों का ओबीसी दर्जा

राष्ट्रीय सुरक्षा

- साइबर अपराधों से निपटने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन

राजव्यवस्था एवं शासन

किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु 3 माह की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

7 मई, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे पर वयस्क या किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाए या नहीं' इसके आकलन हेतु प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए दी गई 3 माह की अवधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसे केवल निर्देश के रूप में माना जाना चाहिए।

- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए तीन महीने की अवधि का प्रावधान 'किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015' की धारा 14(3) के तहत किया गया है, जो इसी अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत जघन्य अपराधों के मामलों से संबंधित है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय **'कानून का उल्लंघन करने वाले बालक की ओर से उसकी माता बनाम कर्नाटक राज्य'** [Child in Conflict With Law Through His Mother Vs The State of Karnataka] नामक वाद में दिया गया है।
  - इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम में जघन्य अपराधों से जुड़े **'कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों'** (Children in Conflict with Law) के **प्रारंभिक मूल्यांकन'** संबंधी प्रावधान पर विचार किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 101(2) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील **'बाल न्यायालय'** (Children's Court) उपलब्ध होने की स्थिति में बाल न्यायालय के समक्ष ही दायर की जाएगी, बावजूद इसके कि वहां 'सत्र न्यायालय' (Court of Sessions) अस्तित्व में हो।
- हालांकि, जिले में ऐसे बाल न्यायालय के गठित न होने की स्थिति में अधिनियम के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति 'सत्र न्यायालय' में निहित मानी जाएगी।
- अदालत ने यह भी माना कि जघन्य अपराधों में प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए धारा 15 के तहत पारित किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 101(2) के तहत अपील 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 को **'कानून का उल्लंघन करने वाले बालक'** (CCL) तथा **'देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों'** (CCP) से संबंधित कानूनों को एक साथ लाकर अधिनियमित किया गया है।
  - **'कानून का उल्लंघन करने वाले बालक'** (CCL) से आशय 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बालक से है, जिस पर अपराध का आरोप है अथवा उसे अपराध करते हुए पकड़ा गया है।
- अधिनियम में, **कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों से जुड़े मामलों के निपटान** हेतु प्रत्येक जिले में **'किशोर न्याय बोर्ड'** (JJB) गठित करने का प्रावधान किया गया।
- **16 वर्ष से अधिक उम्र के बालक द्वारा** कथित जघन्य अपराध के मामले में JJB द्वारा बच्चे की अपराध करने की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है।
- **प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद** किशोर न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए या नहीं।

मतदान डेटा के संबंध में चिंताएं तथा फॉर्म 17सी

24 मई, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मतदान आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाले गैर-सरकारी संगठन (NGO) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर एक याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर याचिका में भारत के चुनाव आयोग को लोक सभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्रवार 'मतदान प्रतिशत संबंधी डेटा' अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
- एडीआर ने अपनी याचिका में मतदान समापन के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक मतदान आंकड़ों और उसके बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता प्रतिशत में काफी अंतर होने की बात कही थी।

सार्वजनिक नीति

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम का एक दशक पूर्ण

1 मई, 2014 को 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014' के लागू होने का एक दशक पूरा हो गया है।

- इस **कानून को स्ट्रीट वेंडर्स (SVs) के वेंडिंग अधिकारों को वैध बनाने** के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य-स्तरीय नियमों एवं योजनाओं के माध्यम से शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की सुरक्षा और विनियमन को सुनिश्चित है।
- यह अधिनियम **स्ट्रीट वेंडर्स तथा सरकार दोनों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों** को स्पष्ट रूप से वर्णित करता है।
- इसके तहत वेंडिंग जोन में सभी **'मौजूदा' विक्रेताओं को समायोजित** करने और **वेंडिंग प्रमाणपत्र** (VC) जारी करने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- अधिनियम **में टाउन वेंडिंग समितियों** (TVC) के माध्यम से एक **'सहभागी शासन संरचना'** को स्थापित करने की वकालत की गई है।
- **टाउन वेंडिंग समितियों** (TVC) में स्ट्रीट वेंडर्स सदस्यों की **भागीदारी 40%** होनी चाहिए, जिसमें **33% महिला SVs** का उप-प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- इन समितियों का विस्तार वेंडिंग जोन में सभी मौजूदा विक्रेताओं तक किया जाना चाहिए।
- अधिनियम **शिकायतों और विवादों को संबोधित करने के लिए तंत्र की रूपरेखा** तैयार करता है, जिसमें एक सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति की स्थापना का प्रस्ताव है।
- इसमें प्रावधान है कि **राज्य/यूएलबी (State/ULBs) प्रत्येक 5 वर्ष** में कम से कम एक बार SVs की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित करेंगे।
- भारत में **50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स हैं।** देश में **सबसे अधिक स्ट्रीट वेंडर्स उत्तर प्रदेश** (लगभग 8.5 लाख) में हैं।
- **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि** (PM Swanidhi) योजना को 01 जून, 2020 को **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय** द्वारा आरंभ किया गया था
- इसका **उद्देश्य कोविड-19 लॉकडाउन** के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना था।
- यह एक **माइक्रो-क्रेडिट सुविधा** है जो स्ट्रीट वेंडरों को एक वर्ष की अवधि के लिए कम ब्याज दरों (12% से कम) के साथ 10,000 रुपये का **संपार्श्विक-मुक्त ऋण** प्रदान करती है, जिससे वेंडरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है।
- योजना की अवधि शुरू में मार्च 2022 तक थी। इसे **दिसंबर 2024 तक** बढ़ा दिया गया है।

सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019' के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी किया है।

- केंद्रीय गृह सचिव ने एक **निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से** लोगों द्वारा किए गए आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित करने के पश्चात नई दिल्ली में प्रथम **14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र** सौंपे।
- 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019' के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए **हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई** (लेकिन मुस्लिम नहीं) अप्रवासियों के लिए अवैध अप्रवासी (जो बिना दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं) की परिभाषा में संशोधन किया गया है।
- ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रावधान है कि **उन्हें 5 वर्ष** (पूर्व में 11 वर्ष) **में फास्ट ट्रैक आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान** की जाएगी।
- 2019 के अधिनियम के माध्यम से **'नागरिकता अधिनियम, 1955' में संशोधन** किया गया है।
- इसमें **OCI कार्ड धारक** द्वारा नागरिकता अधिनियम या लागू किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में उसके **'भारत के विदेशी नागरिक'** (OCI) **पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान** है।
- यह अधिनियम **संविधान की छठी अनुसूची** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। यह अनुसूची **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम** में स्वायत्त आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित है।
- इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम उन राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम) पर लागू नहीं होगा जहां **इनर-लाइन परमिट व्यवस्था** है।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक

धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर EAC-PM की रिपोर्ट

मई 2024 में, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा 'धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा: एक देश-वार विश्लेषण' (1950-2015) [Share of Religious Minorities: A Cross-Country Analysis (1950-2015)] नामक रिपोर्ट जारी की गई।

- इसके अनुसार वर्ष **1950** और 2015 के बीच भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 7.82% की गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में मुस्लिम समुदाय की आबादी में 43.15% की वृद्धि हुई है।

वैश्विक निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर वर्ष 1950 में लगभग **75% जनसंख्या बहुसंख्यक** धार्मिक संप्रदायों से संबंधित थी; **वर्ष 2015 तक यह आंकड़ा लगभग 22% कम** हो गया। **OECD देशों में यह गिरावट औसतन 29%** थी।
- अध्ययन की अवधि (1950 से 2015) में **'आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन'** (OECD) के 38 देशों की धार्मिक जनसांख्यिकी पर एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 30 देशों में प्रमुख धार्मिक समूह **'रोमन कैथोलिकों' के अनुपात में उल्लेखनीय कमी** देखी गई है।
- 1950 में, **अफ्रीका के 24 देशों में 'जीववाद' या 'स्थानीय मूल'** के लोग धार्मिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय माने जाते थे; किंतु 2015 तक इन देशों में से किसी में भी स्थानीय धर्म के अनुयायी बहुसंख्यक नहीं रहे।
- विश्लेषण के अनुसार, **दक्षिण एशिया में बहुसंख्यक धार्मिक समूहों की जनसंख्या में वृद्धि** हो रही है। साथ ही, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, और अफगानिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों की जनसंख्या में कमी आई है।

भारत से संबंधित निष्कर्ष

- **हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82% की गिरावट** आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या लगभग 79.8% थी।
- **अल्पसंख्यकों में मुस्लिम** जनसंख्या 9.84% से बढ़कर 14.095%; **ईसाई** जनसंख्या 2.24% से बढ़कर 2.36%; **सिख** जनसंख्या 1.24% से बढ़कर 1.85% तथा बौद्ध जनसंख्या 0.05% से बढ़कर 0.81% हो गई है।
- इसके विपरीत, **जैन और पारसी** समुदाय के लोगों की जनसंख्या प्रतिशत में कमी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जैन जनसंख्या 0.45% से घटकर 0.36%; जबकि पारसी जनसंख्या में 85% की गिरावट के साथ यह 0.03% से 0.0004% रह गई है।
- **भारत की कुल प्रजनन दर** (TFR) वर्तमान में 2 के आस-पास है, जो वांछित TFR 2.19 के निकट है। **हिंदुओं के लिए TFR** 1991 में 3.3 से घटकर 2015 में 2.1 और 2024 में 1.9 हो गई। मुस्लिमों के लिए TFR 1991 में 4.4 से घटकर 2015 में 2.6 और 2024 में 2.4 हो गई।

भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट (IS4OM) द्वारा संकलित 2023 के लिए 'भारतीय अंतरिक्ष स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट' (ISSAR) जारी की गई है।

- यह रिपोर्ट **भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों की वर्तमान स्थिति** और **अंतरिक्ष में संभावित टकरावों** के प्रति उनकी भेद्यता का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।
- इसमें बताया गया है कि वैश्विक प्रयासों के माध्यम से **अंतरिक्ष संपत्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि** हुई है। वर्ष 2023 में, विश्व भर में लॉन्च तथा कक्षा में पेलोड तैनाती की संख्या अन्य वर्षों से अधिक रही है।
- सक्रिय उपग्रहों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अंतरिक्ष यातायात के संचालन हेतु **अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन** (STM) की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- हालांकि, हवाई एवं समुद्री यातायात के विपरीत, वर्तमान में **STM के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई भी ढांचा मौजूद नहीं है।**
  - ऐसी स्थिति में, दो सक्रिय उपग्रहों के बीच कक्षा में निकट दृष्टिकोण (Close Approach) का समाधान **अंतर-ऑपरेटर समन्वय** (Inter-Operator Coordination) द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग किया जाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2023 में 212 लॉन्च और ऑन-ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट** के माध्यम से लगभग **3,143 ऑब्जेक्ट** अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इस वर्ष के अंत तक **भारत ने लगभग 127 उपग्रह** का प्रक्षेपण किया है।

सामाजिक परिदृश्य

सामाजिक न्याय

- स्नातकोत्तर डॉक्टरों को 2 वर्ष की बॉन्ड अवधि पूरी करना अनिवार्य
- भारत में गर्भपात कानून

सामाजिक–आर्थिक विकास

- कर्मचारी, GPF कटौती के आधार पर स्वचालित रूप से पेंशन के हकदार नहीं

भारत में सामाजिक समस्याएं

- किशोर साइबर अपराधों से निपटने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान
- भारत में तम्बाकू महामारी
- भारतीय जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता

सामाजिक न्याय

स्नातकोत्तर डॉक्टरों को 2 वर्ष की बॉन्ड अवधि पूरी करना अनिवार्य

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की इस प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की है कि वे अपनी पढ़ाई के बाद 2 वर्ष तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देने के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर तो कर देते हैं, लेकिन बाद में इस दायित्व से बचने का प्रयास करते हैं।

- मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि गरीबों के संसाधनों से प्रशिक्षित डॉक्टर उनकी सेवा करने से मना नहीं कर सकते। न्यायालय ने अपने निर्णय में मेडिकल स्नातकों के लिए सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अनुबंधित सेवा पूर्ण करने की बाध्यता को बरकरार रखा।
- चिकित्सकों द्वारा **उच्च न्यायालय में यह याचिका** प्रशिक्षण के पश्चात **'सर्विस बॉन्ड अवधि' से उन्मुक्ति के लिए** दायर की गई थी।
- **'सर्विस बॉन्ड अवधि' मेडिकल के छात्रों एवं सरकार के बीच एक समझौता** है। इसके तहत चिकित्सकों को एक निश्चित अवधि के लिए किसी क्षेत्र विशेष या सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी सेवाएं देनी होती हैं।
- 'सर्विस बॉन्ड अवधि' की मदद से वंचित और पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती से **सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य देखभाल में समानता सुनिश्चित करने में सहायता** मिलती है।
- **'सर्विस बॉन्ड अवधि' संबंधी प्रावधान के पीछे मुख्य विचार** यह है कि मेडिकल कॉलेजों में करदाताओं से संगृहित राशि द्वारा छात्रों को चिकित्सा शिक्षा दी जाती है। प्रशिक्षण के पश्चात चिकित्सक या स्वास्थ्य देखभाल कर्मी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में गरीबों और इन्हीं करदाताओं को सेवा प्रदान करके उनके प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं।
- हालांकि, 'सर्विस बॉन्ड' की अनिवार्यता में **कुछ नैतिक मुद्दे** संलग्न हैं–
  - यह संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन** है। यह अनुच्छेद देश के प्रत्येक नागरिक को कोई भी वृत्ति, उप-जीविका, व्यापार या कारोबार करने का मूल अधिकार प्रदान करता है।
  - जबरन सेवा प्रदान करने का दायित्व **एक पेशेवर की अपने कर्तव्य के प्रति अभिप्रेरणा, रोजगार की संतुष्टि और समग्र प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित** कर सकता है।
  - **'सर्विस बॉन्ड'** जैसे प्रावधान **प्रतिभाशाली व्यक्तियों को** स्वास्थ्य देखभाल सेवा में **करियर बनाने से हतोत्साहित** कर सकते हैं।

भारत में गर्भपात कानून

15 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 20 वर्षीय अविवाहित महिला की 27 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी जीने का मौलिक अधिकार है।

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के तहत, 24 सप्ताह से अधिक अवधि के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब मेडिकल बोर्ड द्वारा भ्रूण में गंभीर असामान्यता की पहचान की गई हो या गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से इस प्रकार की सद्भावपूर्वक राय दी गई हो।
- भारत में गर्भपात पर कानून मुख्य रूप से **'भारतीय दंड संहिता' की धारा 312-316** और **'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट, 1971'** के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
- **MTP अधिनियम 1971, के तहत** कुछ अनुमेय आधार निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर एक महिला गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (Medical Termination) कर सकती है। यह व्यवस्था गर्भपात के खिलाफ सामान्य कानून में एक अपवाद है।
- **मार्च 2021 में संसद ने MTP अधिनियम, 1971** में संशोधन करने के लिए **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021** पारित किया था, जो सितंबर 2021 में लागू हुआ।
- **MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021** ने व्यापक देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय, यूजेनिक, मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित अ ैर कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है।

कल्याणकारी योजनाएं

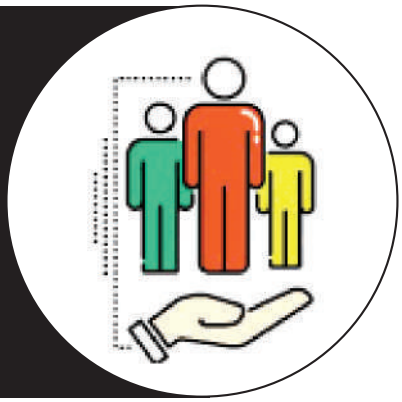

PM-WANI योजना की प्रगति

हाल ही में, दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-Vani) योजना के तहत दूरसंचार विभाग और C-DOT ने मिलकर पूरे देश में करीब 2 लाख (1,99,896) पब्लिक Wi-Fi हॉटस्पॉट तैयार कर लिए हैं।

- देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जनता को **सस्ती और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी** प्रदान करने के लिए **दूरसंचार विभाग** (DoT) द्वारा दिसंबर 2020 में PM-WANI योजना शुरू की गई थी।
- यह पहल **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018** (NDCP, 2018) के एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लक्ष्य के अनुरूप है।
- WAPs एक **ओपन-आर्किटेक्चर प्रणाली** पर काम करेगा, जिससे कई सेवा प्रदाता एक ही मंच के माध्यम से जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
- PM-WANI इकोसिस्टम में **चार भाग** होते हैं: पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA), ऐप प्रोवाइडर और सेंट्रल रजिस्ट्री।
- **PDO** वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करता है और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पहुंच प्रदान करता है। इन सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से **ब्रॉडबैंड इंटरनेट** प्रदान करने के लिए पीडीओ को दूरसंचार विभाग से किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
- **PDOA** द्वारा PDO को **प्राधिकरण और लेखा सेवाएं** प्रदान की जाती हैं। PDOA उपयोगकर्ता को प्लान खरीदने और उनके डेटा खपत पर नजर रखने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। PDOA को कोई लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- **छोटे दुकानदार** अंतिम छोर तक पहुंच सेवा प्रदाता के रूप में **PDO बन सकते** हैं और इंटरनेट और बैकएंड सेवाओं के लिए **PDOA से सेवाएं** ले सकते हैं।
- ऐप प्रोवाइडर द्वारा उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने के लिए एक एप्लिकेशन विकसित करना होता है। स्टार्टअप और वॉलेट प्रदाता ऐप प्रदाता बन सकते हैं।
- **सेंट्रल रजिस्ट्री** की देखरेख सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (CDoT) द्वारा की जाती है, यह PDOA का विवरण रखती है।
- **इस योजना का लक्ष्य** सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (PDO) द्वारा स्थापित वाई-फाई एक्सेस पॉइंट (WAP) के निर्माण के माध्यम से देश भर में एक सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करना है।
- PM-WANI योजना के तहत सार्वजनिक हॉटस्पॉट तक पहुंचने के लिए, किसी को एक प्रासंगिक ऐप डाउनलोड करना होगा जो उपलब्ध नेटवर्क दिखाता है।
- इसके बाद उपयोगकर्ता उपलब्ध कनेक्शनों की सूची में से चुन सकता है और नेटवर्क का उपयोग करने के लिए भुगतान कर सकता है।
- उपयोगकर्ता तब तक नेटवर्क का उपयोग कर सकता है जब तक उसका बैलेंस खत्म न हो जाए।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 113 सड़कों को मंजूरी दी है।

- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है जिसे **वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26** तक लागू किया गया है।
- इसके तहत **देश की उत्तरी सीमा पर स्थित 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश** और **1 केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख** के 19 जिलों के 46 प्रखंडों के चिन्हित गांवों के व्यापक विकास की परिकल्पना की गई है।
- परियोजना के तहत गांवों में **आवश्यक बुनियादी ढांचे** के विकास और **आजीविका के अवसरों** के निर्माण के लिए धन प्रदान जाएगा, जिससे चिह्नित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के **जीवन की गुणवत्ता में सुधार** होगा।
- इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने **मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित** करने और इन गांवों से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा।
- इसमें **पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास और उद्यमशीलता** को बढ़ावा देने और कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की खेती आदि सहित सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसर पैदा करने के लिए चयनित गांवों में हस्तक्षेप के केंद्रित क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है।
- इसके तहत **परिकल्पित परियोजनाओं** में असंबद्ध गांवों को सड़क कनेक्टिविटी, आवास और गांव के बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, टेलीविजन और दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करना भी शामिल है।
- **ग्राम पंचायतों की मदद से** जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट ग्राम कार्य योजना बनाई जाएगी और केंद्र और राज्य योजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) का **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** (BADP) के साथ कोई **ओवरलैप नहीं** होगा।

विरासत एवं संस्कृति

ऐतिहासिक व्यक्तित्व

- रबींद्रनाथ टैगोर
- राजा रवि वर्मा एवं इंदुलेखा पेंटिंग

कला एवं संस्कृति

- तीन भारतीय कृतियां यूनेस्को के MOW एशिया-पैसिफिक रजिस्टर में शामिल
- बुद्ध पूर्णिमा
- गंगम्मा जतारा
- चिथिराई महोत्सव

ऐतिहासिक साक्ष्य

- श्री माधव पेरुमल मंदिर एवं इसके शिलालेख

ऐतिहासिक व्यक्तित्व

रबींद्रनाथ टैगोर

8 मई, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगाली कैलेंडर के अनुसार टैगोर जयंती बोइशाख (Boishakh) महीने के 25वें दिन मनाई जाती है।

- रबींद्रनाथ टैगोर एक **महान कवि, लेखक, दार्शनिक, उपन्यासकार** थे। उनका जन्म 7 मई, 1861 को हुआ था और वह ब्रह्म समाज के नेता देवेन्द्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे।
- इन्हें **'गुरुदेव'** (Gurudev), **'कबीगुरू'** (Kabiguru) और **'बिस्वकाबी'** (Biswakabi) के नाम से भी जाना जाता है। डब्लू.बी. येट्स (W.B Yeats) द्वारा रबींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट एवं रचनात्मक कलाकार कहा गया है।
- उन्होंने 2000 से अधिक **गीतों की रचना** की है और उनके गीतों एवं संगीत को **'रबींद्र संगीत'** (Rabindra Sangeet) कहा जाता है। उन्हें बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण हेतु उत्तरदायी माना जाता है।
- उनकी **उल्लेखनीय कृतियों** में गीतांजलि, घारे-बैर, गोरा, मानसी, बालका, सोनार तोरी आदि शामिल हैं, साथ ही उन्हें उनके गीत **'एकला चलो रे'** (Ekla Chalo Re) के लिये भी याद किया जाता है। उन्होंने अपनी पहली कविताएं **'भानुसिम्हा'** (Bhanusimha) उपनाम से 16 वर्ष की आयु में प्रकाशित की थीं।
- अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा वे एक **दार्शनिक** और शिक्षाविद भी थे, जिन्होंने वर्ष 1921 में विश्व-भारती विश्वविद्यालय (Vishwa-Bharati University) की स्थापना की जिसने पारंपरिक शिक्षा को चुनौती दी।
- इन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से पेश किया। वे एक असाधारण और प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने **साहित्य एवं संगीत** को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। रबींद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्यरचना गीतांजलि के लिये वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में **नोबेल पुरस्कार** दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर-यूरोपीय थे।
- वे महात्मा गांधी के अच्छे मित्र थे और महात्मा गांधी को उन्होने **'महात्मा'** की उपाधि दी थी। उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र संभव तरीका है। वर्ष 1929 तथा वर्ष 1937 में उन्होंने विश्व धर्म संसद (World Parliament for Religions) में भाषण दिया।
- वर्ष 1915 में उन्हें ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम (British King George V) द्वारा **नाइटहुड** की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जलियांवाला नरसंहार के विरोध में टैगोर ने 1919 में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी।

राजा रवि वर्मा एवं इंदुलेखा पेंटिंग

29 अप्रैल, 2024 को प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्मस्थान त्रावणकोर के किलिमनूर पैलेस (Kilimanoor Palace) में उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग "इंदुलेखा" (Indulekha) की प्रथम वास्तविक प्रति का अनावरण किया गया।

- **इंदुलेखा** 19वीं सदी की पेंटिंग है; इस तेल पेंटिंग में इंदुलेखा को अपने प्रेमी माधवन के लिए एक पत्र पकड़े हुए दर्शाया गया है। 'इंदुलेखा' ओ चंदू मेनन के पहले आधुनिक मलयालम उपन्यास के एक चरित्र पर आधारित है। यह उपन्यास वर्ष 1889 में प्रकाशित हुआ था, जिसके नायक के. माधवन थे।
- राजा रवि वर्मा का जन्म अप्रैल 1848 में केरल के किलिमनूर में एक ऐसे परिवार में हुआ था, जो त्रावणकोर के राजघरानों के बहुत करीब था। उन्हें अक्सर आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है, वे **भारतीय देवी-देवताओं के यथार्थवादी चित्रण** के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं।
- उन्होंने मुख्य रूप से राजघरानों के लिए चित्रकारी की, लेकिन उन्हें अपने प्रिंट और ओलियोग्राफ के माध्यम से कला को आम जनता तक पहुंचाने का श्रेय भी दिया जाता है।
- त्रावणकोर के तत्कालीन शासक अयिलयम थिरुनल (Ayilyam Thirunal) के संरक्षण में, उन्होंने शाही चित्रकार रामास्वामी नायडू से **'जलरंजित चित्रकला'** (watercolour painting) सीखी।
- बाद में उन्होंने डच कलाकार **'थियोडोर जेन्सेन'** (Theodore Jensen) से तैल चित्रकला (Oil Painting) का प्रशिक्षण लिया। वह तेल चित्रों का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कलाकारों में से एक थे।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

उद्योग

- भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक व्यापार सम्मेलन
- 'इस्पात क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने' पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- IIBX का पहला ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्य

बुनियादी ढांचा

- राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा निवेश मॉडल
- परियोजना वित्तपोषण हेतु आरबीआई के मसौदा दिशानिर्देश

संसाधन

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर त्रैमासिक बुलेटिन

विदेशी व्यापार और एफडीआई

- 10 शीर्ष व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत के व्यापार की स्थिति
- मुक्त व्यापार समझौतों पर विमर्श हेतु रणनीतिक बैठक

बैंकिंग और वित्त

- RBI द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण
- बीमाकर्ताओं हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन पर मास्टर सर्कुलर
- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की कार्यप्रणाली में पर्यवेक्षी चिंताएं

भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं

- घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत में गिरावट

उद्योग

भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक व्यापार सम्मेलन

17-18 मई, 2024 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ का 'वार्षिक व्यापार सम्मेलन' (CII Annual Business Summit 2024) आयोजित किया गया।

- सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि **भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को अपने उत्पादों में अधिक 'शोधन'** (Refinement) करने की आवश्यकता है। साथ ही, सरकार इस बात का आकलन करेगी कि इस प्रयास में नीतिगत समर्थन कैसे प्रदान किया जाए।
- वित्त मंत्री के अनुसार भारत को और अधिक **आत्मनिर्भर बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा** देना होगा। साथ ही नीतियों की मदद से भारत को विनिर्माण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी।
- भारत में **उपभोक्ता बाजार 2.9 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के बराबर** अवसर प्रस्तुत करता है। भारत में 2031 तक **भोजन तथा वित्तीय सेवाओं पर खर्च बढ़कर क्रमशः 1.4 ट्रिलियन डॉलर** तथा 670 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इससे कुल मिलाकर 1.39 ट्रिलियन डॉलर के अन्य आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे।
- भारत का **जनसांख्यिकीय लाभांश अगले 30 वर्षों तक बना रहेगा**। इसके लाभ प्राप्त करने के लिए कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत में विनिर्माण क्षेत्र

- **ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और उपभोक्ता टिकाऊ** वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्रदर्शन के कारण, विनिर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास के एक अभिन्न स्तंभ के रूप में उभरा है।
- देश की **जीडीपी में 17% तथा 27.3 मिलियन से अधिक श्रमिकों के** आधार के साथ, विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत के पास **2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान निर्यात करने की क्षमता** है और यह एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की राह पर है।
- भारतीय **विनिर्माण क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 में 11.6% की वृद्धि** के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है।
- वित्त वर्ष 2023 के दौरान **विनिर्माण निर्यात में 6.03% की वृद्धि** के साथ 447.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निर्यात दर्ज किया गया है।

विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास

- **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति** का लक्ष्य 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है।
- विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक विनिर्माण मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए इस क्षेत्र के लिए **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन** (PLI) **योजना** वर्ष 2022 में शुरू की गई थी।
- **केंद्रीय बजट 2023-24 में** की गई घोषणा के माध्यम से विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न नवीन सहकारी समितियों के लिए आयकर की दर 22% से घटाकर 15% कर दी गई है।
- **रक्षा मंत्रालय** ने 2025 तक एयरोस्पेस और **रक्षा विनिर्माण में 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य** रखा है, जिसमें 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात भी शामिल है।
- भारत सरकार का अनुमान है कि वर्ष **2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का हो जाएगा।
- **मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया** जैसी पहलों ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

वैश्विक मुद्दे

- स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता

अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते

- चाबहार बंदरगाह टर्मिनल के संचालन हेतु भारत-ईरान समझौता
- यूरोप का 'एआई कन्वेंशन'

अंतरराष्ट्रीय संगठन

- आतंकवाद-रोधी ट्रस्ट फंड में भारत का योगदान
- भारतीय सांसद के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कलर नोटिस
- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- भारत-नेपाल सीमा विवाद

मानचित्र के माध्यम से

- दारफुर संकट
- इजरायली रक्षा बलों का राफा शहर में अभियान

वैश्विक मुद्दे

स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता

28 मई, 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले नवीनतम देश बन गए, जिससे फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है।

- इससे **इजराइल पर शांति वार्ता शुरू करने का दबाव** बढ़ गया है। हालांकि इजराइल ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिए जाने वाले **कदम की आलोचना** की है।
- हाल ही में, **ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के सदस्य माल्टा** ने भी संकेत दिया है कि वे जल्द ही ऐसा कर सकते हैं।
- अभी तक **संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान तथा दक्षिण कोरिया** द्वारा इसे एक राज्य के रूप में **मान्यता नहीं दी गई** है।
  - हालांकि, वे इस बात पर जोर देते हैं कि फिलिस्तीनी द्वारा राज्य का दर्जा बातचीत के जरिए किए गए समाधान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।
  - किंतु, वर्ष 2009 के बाद से इस दिशा में कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है।
- वर्ष **1974 में भारत** फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को मान्यता देने वाला **पहला गैर-अरब राज्य** बन गया था। तभी से भारत एवं फिलिस्तीन के मध्य सामान्य संबंध बन रहे हैं।
  - आगे चलकर, वर्ष 1988 में भारत द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान की गई, और यह ऐसा करने वाले अग्रणी देशों में शामिल था।
  - वर्ष 1996 में भारत ने गाजा शहर में फिलिस्तीन के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया।
  - **भारत इजराइल एवं फिलिस्तीन** के मध्य शांति एवं सुरक्षा की वकालत करता रहा है। भारत दोनों देशों की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का समर्थन करता है। साथ ही, विवादित मुद्दों को आपसी बातचीत से हल करने की बात करता रहा है।
- **1948 में** संयुक्त राष्ट्र के एक निर्णय द्वारा इजराइल के पड़ोस में एक फिलिस्तीनी राज्य की परिकल्पना की गई थी।
- 1993 में ओस्लो, नॉर्वे में इजरायली और फिलिस्तीनी नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर बातचीत हुई।
  - इस प्रक्रिया के तहत, इजरायली सरकार और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) **'दो-राज्य समाधान'** लागू करने की योजना पर सहमत हुए।
- फिलिस्तीन राज्य को वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते

चाबहार बंदरगाह टर्मिनल के संचालन हेतु भारत-ईरान समझौता

13 मई, 2024 को, भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सामान्य सहयोग ढांचे की प्रारंभिक स्थापना के 8 वर्ष बाद हुआ है।

- **अनुबंध पर इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड** (IPGL) और **ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन** (PMO) के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- **IPGL ने** बंदरगाह और उसके बुनियादी ढांचे को सुसज्जित करने में लगभग 120 मिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन की क्रेडिट विंडो (Credit Windo) की पेशकश की है।
- यह समझौता वर्ष 2016 के आरंभिक समझौते की जगह लेगा, जिसमें चाबहार बंदरगाह में **'शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल'** पर भारत के परिचालन को शामिल किया गया था और इसे वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाना था।

पर्यावरण एवं जैव विविधता

जैव विविधता

- पूर्वी घाट के जल निकायों में आक्रामक 'सेलफिन कैटफिश' का प्रसार
- जैव विविधता कन्वेंशन के सहायक निकाय SBSTTA की बैठक

सतत विकास

- उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य पर नैरोबी घोषणा

प्रदूषण

- सीसा संदूषण
- सजीवों में माइक्रोप्लास्टिक
- तेल रिसाव की समस्या से निपटने हेतु संगोष्ठी का आयोजन

जलवायु परिवर्तन

- वेनेजुएला में ग्लेशियर की समाप्ति
- भारत में मानसून का आगमन एवं उत्तर भारत में हीट वेव
- जलवायु परिवर्तन का पृथ्वी के घूर्णन पर प्रभाव

आपदा प्रबंधन

- सूक्ष्मजीवों द्वारा मीथेन का उत्पादन

पर्यावरण संरक्षण

- कृषि भूमि से 6 मिलियन पेड़ गायब हुए

जैव विविधता

पूर्वी घाट के जल निकायों में आक्रामक 'सेलफिन कैटफिश' का प्रसार

हाल ही में, कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (CCMB) द्वारा पूर्वी घाट के जल निकायों पर किये गए अध्ययन में यह पाया गया है कि आक्रामक 'सेलफिन कैटफिश' (Sailfin Catfish) पूर्वी घाट के जल निकायों में 60% तक फैल गई है, जिससे मछली पकड़ने के जाल और पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंच रहा है।

- सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा इसके लिए eDNA-**आधारित मात्रात्मक पीसीआर जांच** (eDNA-based quantitative PCR assay) नामक पद्धति का उपयोग किया गया।
  - इस विधि का उपयोग किसी विशेष वातावरण में मौजूद प्रजातियों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है। इस विधि के तहत मिट्टी, पानी या हवा आदि से उस प्रजाति से संबंधित आनुवंशिक सामग्री को एकत्रित किया जाता है।
- सेलफिन कैटफिश **दक्षिण अमेरिका की मूल मछली प्रजाति** है। वर्तमान में इसे आक्रामक विदेशी प्रजाति मान लिया गया है, जो जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।
- अपनी आक्रामक प्रकृति के कारण इसने अपनी मूल सीमा के बाहर विभिन्न मीठे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में अपनी आबादी का प्रसार किया है।
- इसे भारत के पूर्वी घाट में इसकी अनूठी **शारीरिक बनावट** के कारण छोड़ा गया था। इसके साथ ही इसे टैंकों और एक्वैरियम में शैवाल के विकास को बाधित करने की क्षमता के कारण भी भारत में लाया गया था।
- लेकिन इस प्रजाति की आबादी तेजी से बढ़ती है। इसके साथ ही इनका **जीवनकाल** भी 10 वर्षों से अधिक का है, जो इसे जैव विविधता के लिए एक प्रमुख खतरा बनाता है।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियां अक्सर **स्थानिक प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा** करती हैं या उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
  - ये उस पारिस्थितिक तंत्र की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर सकती हैं।
- **कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र,** वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
  - इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी अनुसंधान और प्रशिक्षण का संचालन करना है।

जैव विविधता कन्वेंशन के सहायक निकाय SBSTTA की बैठक

13-18 मई, 2024 के मध्य केन्या के नैरोबी में जैविक विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity - CBD) के 'वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सलाह पर सहायक निकाय' (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice) की 26वीं बैठक [SBSTTA-26] संपन्न हुई।

- SBSTTA, CBD के सभी अनुबंधित पक्षों के लिए एक बहु-विषयक निकाय है, जो जैव विविधता की स्थिति का वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यांकन प्रदान करता है।

अंतरिक्ष विज्ञान

- ISRO द्वारा तरल इंजन का परीक्षण
- JAXA का LUPEX मिशन
- ब्लू ओरिजिन की मानव अंतरिक्ष उड़ान तथा अंतरिक्ष पर्यटन
- निसार उपग्रह द्वारा पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों पर नजर
- सौर तूफान

जैव प्रौद्योगिकी

- डेंगू के लिए एक नया टीका : TAK-003
- WHO ने बैक्टीरियल पैथोजेन प्राथमिकता सूची को अपडेट किया
- थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम

रक्षा प्रौद्योगिकी

- स्मार्ट मिसाइल प्रणाली

भू–विज्ञान

- पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का खिसकना

अंतरिक्ष विज्ञान

ISRO द्वारा तरल इंजन का परीक्षण

9 मई, 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (Additive Manufacturing) तकनीक के माध्यम से निर्मित तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आमतौर पर 3डी प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है।

- इस रॉकेट इंजन को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के ऊपरी चरण में प्रयोग किया गया है। इसरो द्वारा इस चरण मे पीएस 4 इंजन (PS4 Engine) का प्रयोग किया जाता है। इसरो ने पीएस4 इंजन को फिर से डिजाइन किया था तथा 3डी प्रिंटिंग का उपयोग करके इसका उत्पादन किया।
- विनिर्माण प्रक्रिया में लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक (Laser Powder Bed Fusion - LPBF) का उपयोग किया गया। लेजर पाउडर बेड फ्यूजन (एलपीबीएफ) धातु 3डी प्रिंटिंग तकनीक है जहां एक लेजर धातु के कणों को चुनिंदा रूप से पिघलाता है और एक साथ जोड़ता है। इससे परत दर परत एक 3डी ऑब्जेक्ट बनता है।
- इस प्रौद्योगिकी द्वारा इसरो ने इंजन में पार्ट्स की संख्या 14 से घटाकर एक तक कर दी है। इससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग में काफी बचत हुई है और उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में लगने वाले समय में 60% की कमी आई है।
- इंजन का निर्माण मेसर्स विप्रो 3डी द्वारा किया गया है जो भारतीय कंपनी है। इंजन का परीक्षण इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि (तमिलनाडु) में किया गया था। PS4 इंजन में ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (nitrogen tetroñide) और ईंधन के रूप में मोनोमिथाइल हाइड्राजीन (monomethyl hydrazine) का उपयोग किया गया है।
- 3डी प्रिंटिंग शब्द का प्रयोग आमतौर पर सभी प्रकार के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह एक डिजिटल कंप्यूटर-एडेड डिजाइन फाइल को त्रि-आयामी भौतिक ठोस वस्तु या भाग में बदलने को संदर्भित करता है।
- यह आम तौर पर प्रिंटहेड, नोजल या अन्य प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके सटीक ज्यामितीय आकृतियों में सामग्री परत दर परत जमा करके ऐसा करता है। यह एक योगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए प्लास्टिक, कंपोजिट या जैव-सामग्री जैसी सामग्री की परतें बनाई जाती हैं।

JAXA का LUPEX मिशन

हाल ही में, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन (Lunar Polar Exploration Mission - LUPEX) के अगले कुछ वर्षों में उड़ान भरने की संभावना है।

- मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह का पता लगाना है। इसके साथ ही इस मिशन के द्वारा चंद्रमा की उपसतह पर भी पानी की खोज की जानी है। इस मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाना है। यह मिशन जापान के H3 रॉकेट से उड़ान भरेगा।
- यह चंद्रमा की सतह पर उपस्थित सूखी रेजोलिथ के साथ, ढीली असंगठित चट्टान और धूल की परत आदि की जांच करेगा। यह चंद्रमा पर एक बड़ा रोवर भेजने का JAXA का पहला प्रयास है।
- LUPEX भारत-जापान साझेदारी में सम्पन्न किया जाने वाला एक संयुक्त चंद्रमा मिशन है। चंद्र रोवर जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) लैंडर का विकास कर रहा है जो रोवर को ले जाएगा।
- मिशन में अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अवलोकन उपकरण भी शामिल होंगे, जो इसकी वैज्ञानिक क्षमताओं को और बढ़ाएंगे।
- चंद्रमा अंतरिक्ष में स्थित पृथ्वी के सबसे निकट नजर आने वाला पिंड है। अत: स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष मिशन भेजने का आकर्षण विभिन्न देशों में पाया जाता है। अगस्त 2023 तक चंद्रमा के लिए अब तक 12 देश करीब 141 अभियान चला चुके हैं।
- इनमें से जहां 59 विफल रहे, तो वहीं पांच में आंशिक सफलता मिली, 69 को सफल अभियान माना गया। इनमें से तीन अभियान भारत की ओर से चलाए गए। भारत ने 22 अक्तूबर, 2008 को चंद्रयान-1 मिशन में ऑर्बिटर और इम्पैक्टर भेजे थे, दोनों सफल थे।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा विशेष
अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत के पड़ोसी देश

भारत-श्रीलंकाः प्रमुख मुद्दे और उनका समाधान

श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है और प्रादेशिक सीमा से केवल 30 समुद्री मील दूर है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और भाषाई संबंधों की साझा विरासत 2,500 वर्ष से अधिक पुरानी है। वर्ष 2022 में 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

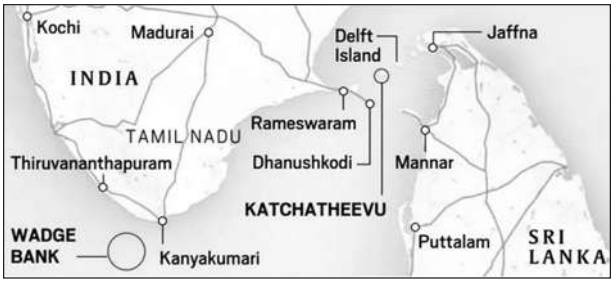

भारत-श्रीलंका के संबंधों में चुनौतियां

- **श्रीलंका में चीनी प्रभावः** समुद्री रेशम मार्ग नीति के हिस्से के रूप में, चीन ने कोलंबो और हंबनटोटा बंदरगाहों का निर्माण किया। यह चीन की समुद्री रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से एक है।
- **मछुआरों की समस्याः** पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी में, दोनों देशों के मछुआरों के भटकने की घटनाएं आम हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के लिए भारतीय मछुआरों की नियमित गिरफ्तारी होती रही है।
- **कच्चाथीवु द्वीपः** भारत 1974 में कच्चाथीवु द्वीप समझौते के तहत इस द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता को मान्यता देता है। हालांकि, तमिलनाडु ने दावा किया कि कच्चाथीवु भारतीय क्षेत्र में आता है।
- **तमिल हितों से संबंधित मुद्देः** श्रीलंका में सिंहली बहुमत और तमिल अल्पसंख्यक के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है जिसने हाल के दशकों में द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है।
- **राजनीतिक अस्थिरताः** श्रीलंका में हाल के वर्षों में सरकार और नेतृत्व में लगातार बदलाव के साथ राजनीतिक अस्थिरता देखी गई है। इससे भारत के साथ जुड़ने और आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने की देश की क्षमता प्रभावित हुई है।

भारत-श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए समाधान

भारत-श्रीलंका संबंधों में सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल हो सकता है, जिसमें कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:

- **आर्थिक सहयोगः** भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (ISFTA) जैसे समझौतों के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ाने से आर्थिक संबंधों में काफी विस्तार हो सकता है।
- **सांस्कृतिक संबंधः** लोगों के बीच करीबी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध धर्म जैसी साझा धार्मिक विरासत जैसे मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोगः** रक्षा संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **बुनियादी ढांचे का विकासः** लोगों से लोगों के बीच संपर्क और व्यापार में सुधार के लिए नौका सेवाओं जैसी कनेक्टिविटी पहल सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से काम करना।
- **बहुपक्षीय सहयोगः** आम चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों और क्षेत्रीय समूहों के साथ मिलकर काम करना।
- **मछुआरों की समस्या का समाधानः** दोनों देशों के मछुआरों के एक-दूसरे के जल क्षेत्र में घुसने की समस्या का स्थायी समाधान खोजना।

निष्कर्ष

भारत-श्रीलंका संबंध बहुआयामी हैं और ऐतिहासिक संबंधों में गहराई से निहित हैं। प्रभावी जुड़ाव, एक-दूसरे की संप्रभुता के प्रति सम्मान, गुजराल सिद्धांत और साझा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता इन अवसरों को भुनाने और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सकारात्मक और स्थायी साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होगी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नः भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों एवं उनके समाधान पर विस्तार से प्रकाश डालें।

हिंद महासागर द्वीपीय राष्ट्र एवं भारत : पहल और प्रभाव

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) 36 तटीय और द्वीपीय देशों में फैला एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों, प्राकृतिक संसाधनों और भू-राजनीतिक महत्व के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा विशेष

राष्ट्रीय सुरक्षा

आतंकवाद/उग्रवाद

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित चुनौतियां : वैश्विक पहलें तथा समाधान

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के तहत वैश्विक स्तर पर हिंसा का उपयोग कर किसी राष्ट्र या समूह द्वारा लोगों को धमकाया जाता हैं या सरकार को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर किया जाता है।

- यह राजनीतिक, वैचारिक, दर्शन आदि से प्रेरित हो सकता है या निहित स्वार्थ पर भी आधारित हो सकता हैं। उदाहरण के लिए, 2001 में न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर पर आतंकवादी हमला, जो कट्टर धार्मिक विचारधारा से प्रेरित माना जाता है।

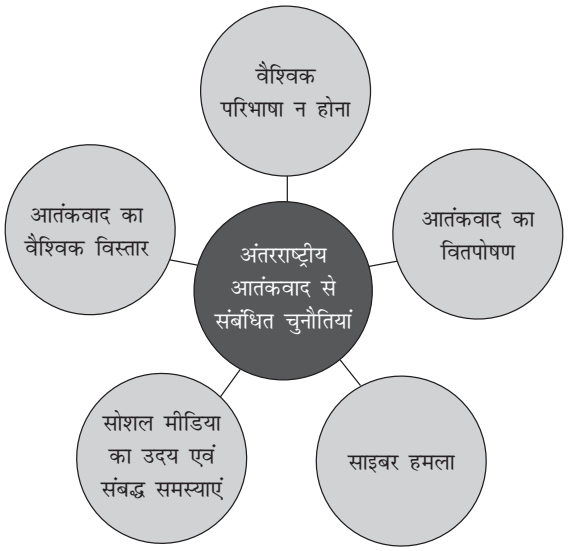

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित चुनौतियां

- **आतंकवाद की कोई वैश्विक परिभाषा नहीं:** अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद की कोई ठोस परिभाषा नहीं है। आतंकवाद के लिये सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा की अनुपस्थिति आतंकवादियों को लाभ प्रदान करती है।
  - इसके साथ ही यह वैश्विक संस्थानों एवं विभिन्न देशों की राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करती है।
- **आतंकवाद का वैश्विक विस्तार:** वर्तमान में विश्व के अधिकांश हिस्सों में आतंकवाद का विस्तार हो चुका है।
  - इसके साथ ही इसका व्यापक तौर पर प्रयोग विभिन्न समूहों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है।
- **सोशल मीडिया का उदय एवं संबद्ध समस्याएं:** इंटरनेट का विस्तार एवं सोशल मीडिया के उदय ने आतंकवादियों को नए सदस्यों की भर्ती करने और अपने उद्देश्य का विस्तार करने हेतु एक नया मंच प्रदान किया है।
  - परंतु इसने वैश्विक स्तर की विभिन्न आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के समक्ष एक नई चुनौती उत्पन्न की है।
- **आतंकवाद का वित्तपोषण:** IMF और विश्व बैंक के अनुसार, अपराधी प्रतिवर्ष अनुमानित 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर का धनशोधन करते हैं।
  - आतंकवादी दान और वैकल्पिक प्रेषण प्रणालियों के माध्यम से अपनी आर्थिक गतिविधियों को छिपाते हैं तथा लगातार वित्त को प्राप्त करते हैं।
- **साइबर हमला:** आतंकवादी अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सरकारों और समाजों को डराने या मजबूर करने के लिये साइबर हमलों का उपयोग करते हैं।
  - इनके द्वारा लोगों की व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारियों को चुराया जाता है तथा इसका प्रयोग अपने घृणित एजेंडा को प्रसारित करने के लिए भी किया जाता है।

नियंत्रण से संबंधित वैश्विक पहलें

- **संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-निरोध कार्यालय (UNOCT):** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-निरोध कार्यालय (United Nations Office of Counter Terrorism-UNOCT) की स्थापना की।
  - यह महासभा के आतंकवाद-रोधी अधिदेशों पर नेतृत्व प्रदान करता है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों में समन्वय तथा सामंजस्य को भी बढ़ावा देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र काउंटर-टेररिज्म ट्रस्ट फंड (UNCTTF):** इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और वर्ष 2017 में इसे संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-निरोध कार्यालय (UNOCT) में शामिल किया गया था।
  - इसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में वैश्विक प्रयासों को सहयोग प्रदान करना है।
- **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF):** FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानीकर्त्ता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में G-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी।
  - अमेरिका पर 9/11 के हमलों के बाद वर्ष 2001 में FATF ने अपने जनादेश का विस्तार कर आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल किया।

राज्य परिदृश्य

इसके अंतर्गत हमने विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों, राज्य स्तर पर आयोजित बैठक एवं सम्मेलनों, सरकारों द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट्स तथा अन्य प्रमुख घटनाक्रमों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है, जिनसे सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

मध्य प्रदेश

भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम

हाल ही में केंद्र सरकार ने भोपाल में पहले शहरी संग्रहालय (City Museum) की स्थापना को मंजूरी दे दी।

- मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल सिटी म्यूजियम की स्थापना मोती महल के बाएं भाग में कर रहा है।
- इस म्यूजियम में पर्यटक 6 जून, 2024 से आदिवासी समुदायों के विविध सांस्कृतिक पहलुओं का अनुभव कर सकते हैं।
- 11 दीर्घाओं वाला प्रस्तावित संग्रहालय भोपाल और मध्य प्रदेश के समृद्ध इतिहास पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसमें प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, पत्थर के औजारों, पुरातात्त्विक खोजों, राजाओं एवं रानियों की पोशाक, प्राचीन मूर्तियों, मंदिर के अवशेष आदि उत्कृष्ट कलाओं का संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा।
- जनजातीय समुदाय की जीवनशैली समझने तथा देखने के लिये संग्रहालय में प्रदेश की सात प्रमुख जनजातियों- गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, सहरिया और कोल के सात घर मौजूद होंगे।
- मध्य प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय मोती महल के दाहिने हिस्से में परमार शासक राजा भोज के सम्मान में एक संग्रहालय भी स्थापित करेगी।

उत्तराखंड

भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान 'नक्षत्र सभा'

हाल ही में, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिये एक नई पहल 'नक्षत्र सभा' शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल-पर्यटन कंपनी 'स्टारस्केप्स' के साथ साथ साझेदारी की है।

- नक्षत्र सभा 1-3 जून, 2024 के मध्य जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी (उत्तराखंड) में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रमों की एक शृंखला शामिल होगी।
- इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिये एक साथ लाना है।
- नक्षत्र सभा तारों को देखने, विशेष रूप से सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगी।
- इसमें विशेषज्ञों के साथ सेमिनार और वेबिनार के अलावा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जिलों में डार्क स्काई संभावित स्थलों को कवर किया जाएगा।
- इस अभियान का लक्ष्य स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

'पिरूल लाओ-पैसे पाओ' मिशन

8 मई, 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 'पिरुल लाओ-पैसे पाओ' मिशन (Pirul Lao-Paise Pao Mission) की शुरुआत की।

- यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है।
- इस मिशन के तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा।
- इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- इसके लिए 50 करोड़ का कॉर्पस फंड अलग से रखा जाएगा।
- पिरूल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। पिरूल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होती हैं।
- इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव में पिरूल के उपयोग से बिजली पैदा करने के लिए 25 किलोवॉट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है।
- भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44% (24,305 वर्ग किमी.) वन है।

उत्तर प्रदेश

यूपी का पहला इको-फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर

16 मई, 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स (CIMAP) ने बाराबंकी के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला 'सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर' लॉन्च किया।

- CIMAP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है।
- यह क्लस्टर कृषि में टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक उदाहरण स्थापित करेगा और देश को शून्य-कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा।

न्यूज़ बुलेट्स

न्यूज बुलेट्स के इस खंड में हम उन समसामयिक घटनाक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, जिनके लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि परीक्षा की तैयारी के लिए इन्हें संक्षिप्त रूप में पढ़ना पर्याप्त होता है। ऐसे घटनाक्रमों को हम पत्रिका के शुरुआती नियमित स्तंभों में शामिल करने के बजाय पृथक रूप से इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय संक्षिप्तिकी

'वैध समारोह के अभाव' में किसी हिंदू विवाह को मान्यता नहीं

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा कि 'वैध समारोह के अभाव' में किसी हिंदू विवाह को 'हिंदू विवाह अधिनियम' के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती।
- जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। इस फैसले के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने 'संस्कार' की प्रथा को मान्यता दी है।

सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता

- हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग (Sela Tunnel) को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- इस सुरंग का निर्माण भारत के 'सीमा सड़क संगठन' द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन 9 मार्च, 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।

आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन

- 21 मई, 2024 को वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बैंगलोर (CHAFB) में एक 'आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली' (EMRS) का उद्घाटन किया गया।
- EMRS पूरे देश में भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारजनों की सेवा के लिए अपनी तरह की पहली 24×7 टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन है। इस प्रणाली का लक्ष्य पूरे देश में कहीं भी आपात स्थिति का अनुभव होने पर कॉल करने वाले को चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवरों की एक टीम द्वारा त्वरित सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का '#PlayTrue अभियान'

- 15-30 अप्रैल 2024 के मध्य भारत की 'राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी' (NADA) द्वारा '#PlayTrue' अभियान चलाया गया, जिसमें 12,133 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ खेलों और डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
- इस अभियान में क्विज और जागरूकता सत्र जैसी गतिविधियों के माध्यम से 'विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी' (WADA) के दृष्टिकोण के अनुरूप निष्पक्ष खेल एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।

रैट-होल खनन

- हाल ही में, असम के तिनसुकिया जिले में पटकाई पहाड़ियों में अवैध रैट-होल खनन वाली खदान में तीन मजदूर फंस गए।
- रैट होल खनन विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रचलित कोयला निष्कर्षण की एक अवैध और खतरनाक विधि है।
- इसमें कोयला निष्कर्षण के लिए छोटी एवं संकीर्ण सुरंगें बनाई जाती हैं, जो केवल इतनी बड़ी होती हैं कि कोई व्यक्ति रेंगकर ही उसमें से निकल सकता है। साइड कटिंग (Side Cutting) तथा बॉक्स कटिंग (Box Cutting) इसके दो प्रमुख प्रकार हैं।

नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स-इन्क्यूबेशन सेंटर

- 20 मई, 2024 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के संयुक्त सचिव द्वारा 'राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद-इन्क्यूबेशन सेंटर (NCB-IC) का उद्घाटन किया गया।
- NCB-IC में व्यावसायीकरण हेतु बाजार के लिए तैयार उत्पादों के विकास एवं सुधार के लिए स्टार्टअप/उद्यमियों को NCB के वैज्ञानिकों तथा सीमेंट एवं निर्माण सामग्री उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाएगी।
- राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (NCB) DPIIT के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन है। यह सीमेंट, संबद्ध निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योगों के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण, शिक्षा और औद्योगिक सेवाओं के लिए समर्पित है।

लघु संचिका

प्रायः सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में नियुक्ति, निधन, पुरस्कारों, चर्चित पुस्तकों, दिवसों आदि से काफी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए संक्षिप्त स्वरूप में समसामयिक घटनाक्रमों का कवरेज पर्याप्त होता है। इसे ध्यान में रखकर हम इस खंड में अति संक्षिप्त रूप में इन समसामयिक घटनाक्रमों का प्रस्तुतीकरण करते हैं।

चर्चित व्यक्तित्व/नियुक्ति

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष

6 मई, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के प्रथम अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई।

- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है।
- यह जीएसटी कानूनों के लिए द्वितीय अपील मंच तथा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान के लिए पहले साझा मंच के रूप में कार्य करेगा।
- यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की तरह कार्य करेगा।
- अंतर-राज्य विवादों को सुलझाने के लिए GSTAT की दिल्ली में एक प्रधान पीठ होगी तथा 31 राज्य पीठ अन्य सभी मुद्दों पर विचार करेंगी।
- उत्तर प्रदेश (UP) में 3 बेंच होंगी, जो भारत में किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं।

कामी रीता शेरपा

22 मई, 2024 को नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी 'माउंट एवरेस्ट' पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

- इन्हें 'एवरेस्ट मैन' के नाम से भी जाना जाता है।
- इससे ठीक 10 दिन पहले 12 मई, 2024 को कामी ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी।
- वरिष्ठ पर्वतीय गाइड कामी रीता ने मई 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी।
- इनका जन्म 17 जनवरी, 1970 को हुआ था।
- 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे।

करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत

4 मई, 2024 को, यूनिसेफ इंडिया [United Nations Children's Fund (UNICEF) India] ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत (National Ambassador) नामित किया।

- इस भूमिका में, वह प्रत्येक बच्चे के बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने में इस गैर-लाभकारी संगठन का समर्थन करेंगी।
- करीना कपूर वर्ष 2014 से यूनिसेफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं, इससे पहले वे सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पर काम कर चुकी हैं।
- यूनिसेफ इंडिया ने जलवायु कार्रवाई, मानसिक स्वास्थ्य और STEM (Science, Technology, Engineering and Math) शिक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए अपने पहले युवा अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की है।
- युवा अधिवक्ताओं में गौरांशी शर्मा, कार्तिक वर्मा, नाहिद आफरीन और विनिशा उमाशंकर शामिल हैं, जो बच्चों और युवाओं के लिए बदलाव ला रहे हैं।

ज्योति रात्रे

19 मई, 2024 को मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गईं।

- इससे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का खिताब संगीता बहल के नाम था, जिन्होंने 19 मई, 2018 को 53 वर्ष की उम्र में 'माउंट एवरेस्ट' पर चढ़ाई की थी।
- यह रात्रे का विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का दूसरा प्रयास था। 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 8,160 मीटर की ऊंचाई से वापस लौटना पड़ा।
- ज्योति रात्रे बोलीविया के पर्वतारोही 'डेविड ह्यूगो अयाविरी क्विस्पे' के नेतृत्व में 8K अभियान (8K Expeditions) की 15 सदस्यीय अभियान टीम का हिस्सा थीं।

निधन

कर्नल वैभव अनिल काले

13 मई, 2024 को संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा सेवा समन्वयक के रूप में कार्यरत रहे भारतीय नागरिक सेवानिवृत्त कर्नल वैभव अनिल काले की गजा के राफा क्षेत्र में, वे जिस वाहन से यात्रा कर रहे थे, उस पर हमले के बाद मृत्यु हो गई।

- 46 साल के कर्नल वैभव अनिल काले नागपुर के मूल निवासी थे।
- कर्नल काले 1998 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे, बाद में

खेल परिदृश्य

खेल जगत में हाल के घटनाक्रमों पर आधारित

टेनिस

इटालियन ओपन 2024

6-19 मई, 2024 के मध्य इटली की राजधानी रोम में इटालियन ओपन, 2024 आयोजित किया गया। इसे प्रायोजन कारणों से 'रोम मास्टर्स' या 'इंटरनैजियोनाली बीएनएल डीइटालिया' के रूप में भी जाना जाता है।

- इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, 2024 का एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने जीता।
- अलेक्जेंडर ज्वेरेव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि इगा स्विएटेक के लिए यह तीसरा इटालियन खिताब था।
- इटालियन ओपन पुरुषों के लिए 'एटीपी मास्टर्स 1000 चैंपियनशिप' तथा महिलाओं के टेनिस खिताब के लिए 'डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट' कही जाती है। यह तीन मास्टर्स 1000 चैंपियनशिप में से एक है, जो क्ले पर खेली जाती है।

इटालियन ओपन 2024 के विजेताओं की सूची

वर्ग	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	अलेक्जेंडर ज्वेरेव	निकोलस जेरी
महिला एकल	इगा स्विएटेक	आर्यना सबालेंका
पुरुष युगल	मार्सेल ग्रैनोलर्स एवं होरासियो जेबालोस	मेट पाविक एवं मार्सेलो अरेवलो
महिला युगल	सारा इरानी एवं जैस्मीन पाओलिनी	कोको गौफ एवं एरिन राउटलिफ

मुक्केबाजी

एलोर्डा कप, 2024

12-19 मई, 2024 के मध्य कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोर्डा कप 2024 (Elorda Cup 2024) का आयोजन किया गया।

- भारत कुल 12 पदकों (2 स्वर्ण, 2 रजत एवं 8 कांस्य) के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा।
- कजाकिस्तान कुल 52 पदक (14 स्वर्ण, 13 रजत एवं 25 कांस्य) के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा और चीन 7 पदक (5 स्वर्ण, 1 रजत एवं 1 कांस्य) के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किग्रा फाइनल में उज्बेकिस्तान की रहमोनोवा सैदाहोन (4-1) को हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।
- विश्व चैंपियन निकहत जरीन ने महिलाओं के 52 किग्रा वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उरकबायेवा को (5-0) हराकर स्वर्ण पदक जीता।

क्रिकेट

KKR ने तीसरी बार IPL का खिताब जीता

26 मई, 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग, (IPL) 2024 का खिताब जीता।

- फाइनल मुकाबला तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया।
- इससे पहले KKR ने 2012 और 2014 में ट्रॉफी जीती थी।
- IPL के 17वें संस्करण का आयोजन 22 मार्च से 26 मई, 2024 के मध्य किया गया।

प्रमुख पुरस्कार	खिलाड़ी
प्लेयर ऑफ द मैच (फाइनल)	मिशेल स्टार्क
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन	नितीश रेड्डी
सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट पुरस्कार	जेक फ्रेजर मैकगर्क
फेयर प्ले अवार्ड	सनराइजर्स हैदराबाद
सीजन की पर्पल कैप	हर्षल पटेल
सीजन की ऑरेंज कैप	विराट कोहली
मोस्टवैल्युएबल प्लेयर ऑफ सीजन	सुनील नरेन

एथलेटिक्स

पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024

17-25 मई, 2024 के मध्य जापान के कोबे में स्थित यूनिवर्सियाड मेमोरियल स्टेडियम में 'पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप' के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया।

- भारतीय टीम चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 5 रजत एवं 6 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 6वें स्थान पर रही।
- पदक तालिका में चीन (87), ब्राजील (42) तथा उज्बेकिस्तान (13) पदकों के साथ क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे।

भारतीय स्वर्ण पदक विजेता	
दीप्ति जीवनजी	स्वर्ण पदक
सिमरन	स्वर्ण पदक
सचिन सर्जेराव खिलारी	स्वर्ण पदक
एकता भयान	स्वर्ण पदक
सुमित अंतिल	स्वर्ण पदक
मरियप्पन थंगावेलु	स्वर्ण पदक

परीक्षा सार

UPSC सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2024

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

परीक्षा तिथि: 21 अप्रैल, 2024

1. दक्कन की जोर्वे संस्कृति के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें, वास्तव में, तटीय कोंकण जिले को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र शामिल है।
2. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवरा गोदावरी घाटियाँ केन्द्रीय क्षेत्र रही हैं।
3. इस संस्कृति के बड़े स्थलों से झूमकृषि के प्रमाण मिलते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- जोर्वे संस्कृति महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृति है, जो तटीय क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे राज्य में फैली हुई है।
- इस संस्कृति के 3 मुख्य केंद्र प्रकाश (तापी घाटी), दैमाबाद (गोदावरी-प्रवरा घाटी) और इनामगांव (भीमा घाटी) है।
- इनामगांव और दैमाबाद सबसे अधिक खुदाई वाले जोर्वे संस्कृति स्थल हैं।
- इस संस्कृति से झूम कृषि के कोई प्रमाण नही मिले है।

2. पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे मदुरैकंची में एक बड़े भव्य नगर के रूप में वर्णित किया गया है, जो तीनों ओर दीवारों से घिरा है और चौथी ओर वैगई नदी है।
2. अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख उत्तम सूती वस्त्रों के केन्द्र के रूप में किया गया है।
3. अन्य साहित्यिक स्रोतों में इसे एक प्रमुख शिल्प केन्द्र के रूप में वर्णित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

- प्राचीन साहित्यिक स्रोतों, जैसे कि संगम साहित्य, मदुरै को मदुरैकंची नामक एक भव्य नगर के रूप में वर्णित करते हैं।
- यह नगर तीन तरफ से दीवारों से घिरा था और चौथी तरफ वैगई नदी बहती थी। अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में मदुरै का उल्लेख उत्तम सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में किया गया है।
- अन्य साहित्यिक स्रोतों में मदुरै को मूर्तिकला, धातु विज्ञान, रत्नकला और हाथी दांत की नक्काशी जैसे शिल्पों का प्रमुख केंद्र बताया गया है।

3. सवाई जय सिंह के खगोलीय कार्य के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्होंने यूरोपीय प्रेक्षणों की सटीकता के बारे में जाना, और डे ला हायर की सारणियाँ प्राप्त कीं, जिनसे उन्होंने एक अपवर्तन सारणी को पुनः तैयार किया।
2. उनके खगोलविदों ने शुक्र की चंद्र कलाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए अपनी दूरबीन भी विकसित की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

- जय सिंह यूरोपीय खगोलविदों के कार्यों से बहुत प्रभावित थे, खासकर फ्रांसीसी खगोलशास्त्री डे ला हायर के कार्यों से।
- जय सिंह ने पांच खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिनमें जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में स्थित वेधशालाएं शामिल हैं।
- इन वेधशालाओं को जंतर-मंतर के नाम से जाना जाता है, और इनमें विभिन्न प्रकार के खगोलीय उपकरण स्थापित किए गए थे।

4. संगीत पर आधारित कृति मान कौतूहल किसके संरक्षण में तैयार की गई ?

(a) ग्वालियर के राजा मान सिंह
(b) तानसेन
(c) मीराबाई
(d) अमीर खुसरो

उत्तर: (a)

- मान कुतुहल राजा मान सिंह तोमर के संरक्षण में बनाए गए एक ग्रंथ का नाम था। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर (1486-1516 ई.) ध्रुपद को शुरू करने और मजबूत करने के पीछे प्रेरक शक्ति थे।

5. सुगम्य भारत अभियान के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कार्यक्रम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है।
2. इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समावेशी समाज का विकास करना है।
3. इसमें दिव्यांगजनों के लिए पेंशन का प्रावधान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1

पत्रिका सार

इस खंड में हम भारत सरकार द्वारा मई 2024 में प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं की परीक्षोपयोगी तथ्यों का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अभ्यर्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

योजना (मई 2024)

भारतीय बुनाई के संबंध में क्षेत्रीय विविधता

आधुनिक भारत में बुनाई की यात्रा का आरंभ देश के सुदूर दक्षिण-पश्चिम में स्थित केरल राज्य से माना जाता है।

- **19वीं सदी के अंत** में रासायनिक रंगों के आगमन से पूर्व तक भारत के सभी भागों में **'श्वेत रंग'** बुनाई का प्रमुख आधार था।
- कई प्रकार के रेशम जिन्हें कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित भारत के अन्य हिस्सों में हाथ से नहीं बुना जाता है; उन्हें कर्नाटक में बेचा जाता है तथा इनको **'डुपियन रेशम'** के नाम से जाना जाता है।
- **पोचमपल्ली इकत अथवा साड़ी** की उत्पत्ति तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले से मानी जाती है। इसमें पारंपरिक ज्यामिति और अमूर्त पैटर्न का उपयोग किया जाता है।
  - भारत सरकार की आधिकारिक एयरलाइंस **'एयर इंडिया' के केबिन क्रू** के पास विशेष रूप से डिजाइन की गई पोचमपल्ली रेशम की साड़ियों का उपयोग किया जाता है।
  - पोचमपल्ली साड़ी को वर्ष 2005 में **'बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण'** अथवा **'भौगोलिक संकेतक'** का दर्जा प्राप्त हुआ था।
- **पैठणी साड़ी** का नामकरण महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित पैठन शहर के नाम पर किया गया है। यहां इसका उत्पादन लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है।
  - इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले रूपांकन में अधिकांश रूप से पारंपरिक **लताएं, फूल एवं फलों की आकृतियां तथा पक्षियों की शैलीबद्ध आकृतियां** शामिल की जाती हैं।
  - **पैठणी साड़ी** की प्रमुख विशेषता यह है कि **इसकी बुनाई हाथ से की** जाती है तथा डिजाइन तैयार करने के लिए किसी भी यांत्रिक साधन का उपयोग नहीं किया जाता है।
- **पाटन पटोला** गुजरात के पाटन क्षेत्र से उत्पन्न एक डबल इकत साड़ी है। इसमें ताने और बाने को लटकते हथकरघे पर बुनाई से पहले धागों की सटीक गिनती के अनुसार बांधा और रंगा जाता है।
  - पटोला रेशम साड़ियां अपने **विविध रंगों, बोल्ड ज्यामिति या डिजाइन** और विविध विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं।
- **कांचीपुरम (तमिलनाडु)** के मंदिरों से प्रेरित होकर साड़ियों को शहतूत रेशम से उत्कृष्ट ढंग से बुना जाता है। इसमें जटिल **'कोरव'** और **'पेटनी'** तकनीक का उपयोग करके ठोस रंग की सीमाएं और पल्लव निर्मित किए जाते हैं।
  - **उत्तम कांचीपुरम साड़ियों** में मोर, हाथी तथा घोड़े जैसे जीवो के शुद्ध जरी अलंकरण और मनमोहक रूपांकन देखने को मिलते हैं। इसमें रुद्राक्षम, थालमपुरिक्कू और मयिल चक्र डिजाइन बनाए जाते है।
- **कोटा डोरिया** कपड़े का नामकरण इसके मूल स्थान कोटा, राजस्थान के नाम पर हुआ है। यह कपड़ा चौकोर चेक पैटर्न में कपास और रेशम का एक अनूठा मिश्रण है।
- एक बुनाई तकनीक के रूप में **'तनचोई बुनाई'** के तहत कपड़े को कवर करते हुए डिजाइन तैयार किया जाता है। **'तनचोई तकनीक'** अपने लघु एवं जटिल पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साटन तनचोई साड़ी इसका प्रमुख उदाहरण है।
- **कुनबी साड़ी** गोवा का पारंपरिक परिधान है। इन्हें मूल रूप से लाल रंग में रंगा जाता था तथा छोटे एवं बड़े चेक में बुना जाता था। इसमें प्रयुक्त की जाने वाली डाई आयरन ओर (Iron ore), चावल कांजी (स्टार्च) और सिरका से बनायी जाती थी।
- **पश्मीना शॉल,** कश्मीरी ऊन से काते गए शॉल का एक अच्छा प्रकार है। यह विशेष ऊन लद्दाख के उच्च पठार की मूल **'चांगथांगी बकरी'** (Capra Aegagrus Hircus) से प्राप्त की जाती है।
- **जामदानी** एक चमकीले पैटर्न वाला सूती कपड़ा है, जिसे पारंपरिक रूप से ढाका के आसपास के शिल्पकारों और प्रशिक्षुओं द्वारा हथकरघे पर बुना जाता है।
  - **जामदानी बंगाल के बेहतरीन मलमल** वस्त्रों में से एक है। जामदानी के ऐतिहासिक उत्पादन को मुगल सम्राटों के शाही वारंटों द्वारा संरक्षण दिया गया था। यह हथकरघा बुनाई के सबसे अधिक समय और श्रम-गहन रूपों में से एक है।
- मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर को **'माहेश्वरी साड़ियों'** का जन्म स्थान माना जाता है। इनकी अनूठी प्रतिवर्ती सीमाएं **'बुगड़ी'** नामक **दो-तरफा बुनाई** के साथ बनाई जाती हैं। इस तरह साड़ी को दोनों तरफ से पहना जा सकता है।
- **मेखला साड़ी,** असम राज्य की एक लोकप्रिय साड़ी है। इसे क्लासिक लहंगे की तरह शरीर के निचले भाग में चारों ओर बेलनाकार रूप में लपेटा जाता है। मेखला साड़ी में **सुंदर सिल्क और जोर्जेट** का उपयोग किया जाता है, जिससे यह श्रृंगारी और भव्य दिखती है।

भारतीय बुनाई में अंतर-सांस्कृतिक प्रभाव

ऐतिहासिक रूप से भारत में बुनाई के प्रमाण प्राचीन **सिंधु घाटी सभ्यता** (3300-1300 ईसा पूर्व) से प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता के अनेक स्थलों पर कपास की खेती और कपड़ा उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

चर्चित शब्दावली

विगत कुछ वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में चर्चित शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। परीक्षा की इसी मांग के अनुरूप समसामयिक सन्दर्भ में चर्चा में रही शब्दावलियों के विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखकर ही हम यह खंड प्रस्तुत कर रहे हैं।

कीलिंग वक्र

कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की वैश्विक औसत सांद्रता मार्च 2024 में 4.7 भाग प्रति मिलियन (ppm) (मार्च 2023 से अधिक) थी, जो किलिंग वक्र में बड़ी वृद्धि को दर्शाती है।

- कीलिंग वक्र 1958 से हवाई के मौना लोआ के ऊपर बना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का माप है।
- यह विश्व में सबसे लम्बे समय तक चलने वाला मापन है।
- स्क्रिप्स CO_2 कार्यक्रम 1956 में चार्ल्स डेविड कीलिंग द्वारा शुरू किया गया था और 2005 में उनकी मृत्यु तक उनके निर्देशन में संचालित किया गया था।

गोल्डेन

गोल्डेन नामक सोने की पत्ती बनाई है- जो विश्व की सबसे पतली सोने की पत्ती है, जो केवल एक परमाणु जितनी मोटी है।

- यह सोने का एक दो-आयामी अपरूप है, जिसका अर्थ है कि इसमें दो-आयामी संरचना में व्यवस्थित सोने के परमाणुओं की एक परत होती है।
- इसे पहले टाइटेनियम कार्बाइड परतों के बीच सिलिकॉन की एक परत रखकर बनाया गया था।
- जब उन्होंने इस सैंडविच संरचना के शीर्ष पर सोना जमा किया, तो सोने के परमाणु पदार्थ में फैल गए और सिलिकॉन परमाणुओं की जगह ले ली, जिससे सोने के परमाणुओं की एक फंसी हुई एकल परत बन गई।
- यह कार्य एक प्राचीन जापानी तकनीक की सहायता से किया गया था, जिसका उपयोग काटने और उच्च गुणवत्ता वाले चाकू बनाने में किया जाता था।

एंटारेस

हाल ही में, बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) ने एंटारेस के सामने से चंद्रमा के गुजरने का फिल्मांकन किया।

- एंटारेस एक आकर्षक तारा है, जिसे अल्फा स्कॉर्पिइ के नाम से भी जाना जाता है।
- यह वृश्चिक (Scorpion) राशि के नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा है, जो प्राचीन संस्कृतियों की आकाशीय विद्या में प्रमुखता से अंकित है। एंटारेस को M1 लाल महादानव तारे का तारकीय वर्गीकरण प्राप्त है।
- M1 पदनाम का अर्थ है कि एंटारेस का रंग लाल है तथा यह अन्य कई तारों की तुलना में अधिक ठंडा है।

डिजिटल गिरफ्तारी

हाल ही में, नोएडा साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ 11 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है और उसे "डिजिटल गिरफ्तारी" का सामना करना पड़ा है।

- डिजिटल गिरफ्तारियां एक प्रकार की परिष्कृत साइबर धोखाधड़ी को संदर्भित करती हैं, जहां साइबर अपराधी कानून प्रवर्तन अधिकारियों या अन्य प्राधिकारियों का रूप धारण कर लेते हैं और पीड़ितों को बड़ी मात्रा में धनराशि हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं।
- संकट की मनगढ़ंत भावना उत्पन्न करके, वे पीड़ितों पर बिना किसी तर्कसंगत विचार या सत्यापन के जल्दबाजी में निर्णय लेने का दबाव डालते हैं।

विशिंग

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने एक परिपत्र जारी कर अपने कर्मचारियों को विशिंग नामक एक परिष्कृत साइबर अपराध के प्रति आगाह किया।
- वॉयस+फिशिंग का संक्षिप्त रूप, विशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक धमकी देने वाला व्यक्ति पीड़ित को फोन कॉल करता है और उसे दुर्भावनापूर्ण फाइलों या ईमेल पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करता है, जो फिर उसे एक वैध दिखने वाली वेबसाइट पर ले जाता है, और उससे व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए कहता है।
- अन्य मामलों में, हमलावर पीड़ित से संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह इतना पेचीदा हो सकता है कि कॉल करने वाला व्यक्ति पीड़ित का मैनेजर या सहकर्मी लग सकता है।

ओपनवाशिंग

- तकनीकी जगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल में "ओपन सोर्स" की अवधारणा पर गरमागरम बहस में उलझी हुई है, जिसमें "ओपनवाशिंग" के आरोप भी लग रहे हैं।
- ओपनवॉशिंग का तात्पर्य कुछ AI कंपनियों के खिलाफ एक आरोप से है कि वे "ओपन सोर्स" लेबल का बहुत शिथिल उपयोग कर रहे हैं।
- समर्थक ओपन-सोर्स एआई के समानता और सुरक्षा लाभों के पक्ष में तर्क देते हैं, जबकि आलोचक इसके दुरुपयोग की संभावना पर प्रकाश डालते हैं।
- इस लेबल को लागू करने वाले संगठनों के खुलेपन के प्रति दृष्टिकोण में काफी भिन्नता हो सकती है, जिसमें न्यूनतम प्रकटीकरण से लेकर सख्त प्रतिबंध तक शामिल हो सकते हैं। ■■

संसद प्रश्नोत्तरी

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य: वनलाइनर रूप में

इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2023

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) द्वारा भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर कौनसी रिपोर्ट तैयार की गई है? – **इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023**
- इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2023 के अनुसार वर्ष 2022 और वर्ष 2050 के बीच 80+ वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या लगभग कितनी बढ़ने की संभावना है? – **279%**
- 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' किस पर आधारित है? –**भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा**
- विश्व का कौन सा संस्थान जनसंख्या से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षण के लिए समर्पित है? – **इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS)**
- इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्ध आबादी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां कौनसी है?
  – **वृद्ध आबादी का स्त्रीकरण और ग्रामीणीकरण**

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया?
  – **सितंबर 2021**
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी कौनसी है?
  – **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)**
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है?
  – **मुक्त परस्पर संचालन योग्य डिजिटल मानकों के अनुरुप एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना**

ओएनजीसी द्वारा गैस की खोज

- ओएनजीसी द्वारा हाल ही में नए हाइड्रोकार्बन की खोज कहां की गई है? – **बंगाल की खाड़ी में**
- भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य बना रहा है? – **15 प्रतिशत**

रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना

- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना की शुरुआत कब की गई?
  – **8 मई, 2020**
- घरेलू रक्षा और ऐरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौनसी स्कीम शुरू की गई है? – **रक्षा अवसंरचना स्कीम**
- योजना के तहत पांच वर्षों के दौरान अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने मूल्य के परिव्यय की घोषणा की गई है? – **400 करोड़ रुपये**
- सरकार ने योजना के तहत किस राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारा (DIC) स्थापित करने की भी घोषणा की है?
  – **उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु**

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- देश भर में गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व जांच सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? – **2016**
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित, व्यापक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसव-पूर्व देखभाल हर महीने में किस तारीख को दी जाती है? – **प्रत्येक माह की 9 तारीख**
- 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
  – **प्लेज फॉर नाइन स्कीम (Pledge for 9 Scheme)**
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) का उद्देश्य है?
  – **गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वतंत्र जांच प्रदान करने के साथ स्वस्थ बच्चे को जन्म देना**

पीएम- प्रणाम

- धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) को कब मंजूरी दी गई? – **28 जून 2023**
- पीएम-प्रणाम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
  – **कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देना**

मनोदर्पण पहल

- 21 जुलाई, 2020 को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस पहल की शुरुआत की गई? – **मनोदर्पण पहल**
- मनोदर्पण नामक पहल का उद्देश्य क्या है?
  – **देश भर में विद्यार्थियों उनके परिवारों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य हेतु मनोसामाजिक सहायता**

राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो

- राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरों राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किये गये अपराध संबंधी आंकड़ों को किस नाम से प्रकाशित करता है? – **'क्राइम इन इंडिया'**
- भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत "पुलिस और लोक व्यवस्था" राज्य के विषय है? –**सातवीं अनुसूची**

फैक्ट शीट

इस खंड के तहत हम उन विषय-वस्तुओं को कवर करते हैं, जो प्रतियोगीता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे परीक्षाओं में बार-बार तथ्य एवं आंकड़े संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं।

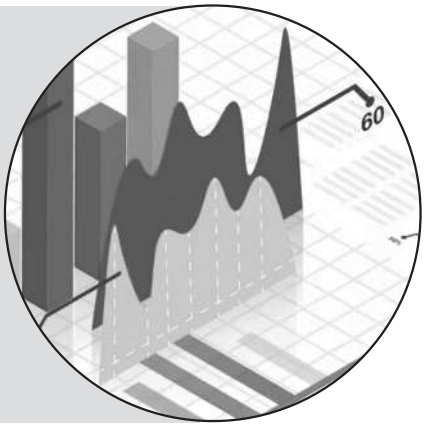

भारत का गेमिंग क्षेत्र

बाजार का आकार

- भारत में दुनिया भर में सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स बाजार है, जिसका यूजर बेस 180 मिलियन है।
- पूर्वानुमानों से पता चलता है कि उद्योग में 33% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ मजबूत वृद्धि होगी, जिसके वित्त वर्ष 2027 तक 25,300 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
- 2023 में 144 मिलियन से 2028 तक 240 मिलियन तक गेमर्स को भुगतान करने का अनुमान है।

उद्योग परिदृश्य

- भारत में 1,400 से अधिक गेमिंग कंपनियां हैं, जिनमें 500 गेमिंग स्टूडियो शामिल हैं।
- 2028 तक पेशेवर खिलाड़ियों की संख्या 2.5 गुना बढ़ जाएगी।
- ई-स्पोर्ट्स को सरकार की मान्यता और राज्य द्वारा संचालित प्रतिभा विकास पहलों से विकास को बढ़ावा मिलेगा।

गेम डाउनलोड और उपभोक्ता आधार

- भारत में मोबाइल गेमिंग का बोलबाला है, जो गेमिंग बाजार का 90% हिस्सा है।
- यह अमेरिका से बिल्कुल अलग है, मोबाइल गेमिंग की हिस्सेदारी लगभग 37% है और चीन में इसकी बाजार हिस्सेदारी का 62% हिस्सा है।
- भारत में गेम डाउनलोड 2019 में 5.65 बिलियन से बढ़कर 2023 में 9.5 बिलियन हो गया।

जनसांख्यिकी और प्राथमिकताएं

- 18 से 30 वर्ष की आयु के लगभग 50% गेमर्स शूटिंग गेम जैसे मिड-कोर और हार्डकोर शैलियों को पसंद करते हैं।
- 31 से 45 वर्ष की आयु के 30% गेमर्स रणनीति गेम पसंद करते हैं।

नौकरी बाजार और आउटसोर्सिंग

- ऑनलाइन गेमिंग उद्योग अगले 10 वर्षों में 2.5 लाख से अधिक नौकरियां जोड़ेगा।
- वर्तमान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख कुशल गेमिंग पेशेवरों को रोजगार देता है।

भारत में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र

बाजार परिदृश्य

- भारत में घरेलू परिधान और वस्त्र उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है।

रैंकिंग

- **कपास और जूट:** भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- **रेशम:** भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है, जिसकी विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़ों में 95% हिस्सेदारी है।
- **दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता:** भारत में कपड़ा और परिधान उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।
  - जो 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और संबद्ध उद्योगों में 10 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

विकास के कारक

- विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की मौजूदगी।
- तकनीकी वस्त्रों पर अधिक ध्यान।
- कच्चे माल की प्रचुरता और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता।
- संपूर्ण मूल्य शृंखलाओं और बड़े और बढ़ते घरेलू बाजार की मौजूदगी।
- प्रतिस्पर्धी विनिर्माण लागत और संगठित खुदरा परिदृश्य और ई-कॉमर्स।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उच्च व्यय योग्य आय और ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं।

प्रमुख वस्त्र और परिधान क्लस्टर

- **कताई क्लस्टर :** लुधियाना, बद्दी, कोयंबटूर, इरोड, गुंटूर।
- **हथकरघा क्लस्टर :** सूरत, तारापुर, मुंबई, अमरावती, अहमदाबाद।
- **बुनाई क्लस्टर :** दिल्ली, लुधियाना, तिरुपुर।
- **परिधान विनिर्माण क्लस्टर :** दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, वापी, विशाखापत्तनम। ■■

समसामयिक प्रश्न

मई 2024 के घटनाक्रम पर आधाारित

1. अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर (SOrTeD) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अग्निबाण SOrTeD अग्निलेट इंजन से लैस एक सिंगल-स्टेज रॉकेट है।
2. इंजन आंशिक रूप से 3D-प्रिंटेड, सिंगल-पीस और सेमी-क्रायोजेनिक है।
3. मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर, रॉकेट को एकल या दो-चरण लॉन्चर के रूप में कॉन्फिगर किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया।
2. यह 'प्रोजेक्ट भीष्म' नामक व्यापक पहल का एक हिस्सा है।
3. इस परीक्षण का उद्देश्य पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात करना है।
4. भारतीय वायु सेना द्वारा पहली बार इस प्रकार के पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) कथन 1 और 3
(b) कथन 2, 3 और 4
(c) कथन 1, 2 और 3
(d) कथन 1, 2, 3 और 4

3. 'अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) अधिनियम' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधि नियम 10 मई, 2024 से लागू हुआ।
2. इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों के प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देना है।
3. अधिनियम में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ को रक्षाकर्मियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सत्य विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

4. चाबहार बंदरगाह टर्मिनल के संचालन हेतु भारत-ईरान समझौता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. यह समझौता सामान्य सहयोग ढांचे की प्रारंभिक स्थापना के 18 वर्ष बाद हुआ है।
3. चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जोड़ने का कार्य करेगा।
4. चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में कौन सा/से विकल्प सही है?

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी।

5. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. **कथन (A):** हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू समुदाय के भीतर विभिन्न पहलुओं से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करके हिंदू विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है।
2. **कारण (R):** हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए न्यूनतम आयु दूल्हे के लिए 21 वर्ष और दुल्हन के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(d) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

6. हाल ही में खबरों में रही, काँवर झील के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अतिक्रमण के कारण धीरे-धीरे यह झील लुप्त हो रही है।
2. यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है, जो कोसी नदी के विसर्प के कारण बनी है।
3. यह झील एशिया की सबसे छोटी मीठे जल की गोखुर झील भी है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सत्य विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

7. भारत की पहली खगोल पर्यटन अभियान 'नक्षत्र सभा' हाल ही में किस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई?

(a) लक्षद्वीप (b) लद्दाख
(c) उत्तराखंड (d) हिमाचल प्रदेश

करेंट अफेयर्स वनलाइनर

सरकारी समाचार सेवाओं-PIB, AIR इत्यादि से संकलित

राष्ट्रीय घटनाक्रम

- 9-10 मई, 2024 को नई दिल्ली में सशस्त्र बलों की संयुक्तता और एकीकरण पर 'परिवर्तन चिंतन-II' सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? - **सीडीएस जनरल अनिल चौहान**
- अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) अधिनियम किस तिथि से लागू किया गया है? - **10 मई, 2024**
- हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल (ZWL) प्रमाणन हासिल कर लिया है? - **तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा**
- 19 मई, 2024 को कौन ब्लू ओरिजिन के एनएस-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर 'पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक' बन गए? - **गोपी थोटाकुरा**
- हाल ही में, किसने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की दो सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं? - **भारतीय सेना**
- हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? - **सेला सुरंग**
- 17 मई, 2024 को इस्पात मंत्रालय ने कहां पर "इस्पात क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? - **विज्ञान भवन, नई दिल्ली**
- 16 मई, 2024 को कौन 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन' (SCBA) के नए अध्यक्ष चुने गए? - **कपिल सिब्बल**
- केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को कब नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किए? - **15 मई, 2024 को**
- हाल ही में किन भारतीय ग्रंथों को 'यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है? - **रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक-लोकन**
- 11 मई , 2024 को किस प्रसिद्ध पंजाबी कवि का 79 वर्ष की आयु में पंजाब के लुधियाना में निधन हो गया? - **सुरजीत पातर**
- हाल ही में किसे उन 10 असाधारण व्यक्तियों में नामित किया गया है, जिन्हें कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय (McGill University) से मानद उपाधि प्राप्त होगी? - **डॉ. सौम्या स्वामीनाथन**
- 11 मई, 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागार, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 2024 की थीम क्या थी? - **सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना**
- 11 मई, 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने 'समाज के लिए परमाणु: जल, भोजन और स्वास्थ्य की सुरक्षा' (Health) विषय पर दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन कहां किया? -**मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)**
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 मई, 2024 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ दिलाई? - **सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा**
- हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 'महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन' में खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ज्ञान आधारित सहयोग प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? - **शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन**

आर्थिक घटनाक्रम

- 17 मई, 2024 को किसके द्वारा नई दिल्ली में पहली बार 'ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव' (ONDC Startup Mahotsav) का आयोजन किया गया? - **उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)**
- 9 मई, 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत दो पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? - **ड्रोन दीदी योजना**
- 7 मई, 2024 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन, 2024 का शुभारंभ कहां किया है? - **नई दिल्ली में**
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने हाल ही में किस बुलियन एक्सचेंज के पहले 'ट्रेडिंग-सह-क्लियरिंग सदस्य' बनने की घोषणा की है? - **इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX)**
- सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिए हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने हेतु वित्त वर्ष 2024 में कितने मूल्य की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की है? - **20,000 करोड़**
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने 2 मई, 2024 को जारी अपनी नवीनतम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? - **6.6%**
- हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने में सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया है? - **बैंक ऑफ नामीबिया (BON)**